



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर



झारखंड में
बिना पैसे के
कुछ नहीं होता
राष्ट्रीय-10

www.dailypioneer.com

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को लगाई फटकार

पराली जलाने से प्रदूषण पर रोक न लगा पाने को लेकर अदालत गंभीर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने को लेकर शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएनयूएम) को फटकार लगाई तथा कहा कि इसे और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति अबय एस.ओका और न्यायमूर्ति अमरेंद्र जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष जताते हुए कहा कि सीएनयूएम को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, अधिनियम का बिल्कुल ही अनुपालन नहीं किया गया है। कृपया हमें एक भी निर्देश दिखाएं जो किसी हितधारक को अधिनियम के तहत जारी किया गया हो। शीर्ष अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि हालांकि आयोग ने कदम उठाए हैं लेकिन उसे और सक्रिय होने



की जरूरत है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कोशिशें और उसके द्वारा जारी निर्देश प्रदूषण की समस्या को कम करें।
न्यायालय ने कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि पराली जलाने के विकल्प के रूप में उपकरणों का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर हो। पीठ ने कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए कि पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए उपकरणों का किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाए। शीर्ष अदालत

ने आयोग को एक बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और विषय की सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। केंद्र की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सालिसीट जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पराली जलाने से रोकने के लिए जारी परामर्श और दिशानिर्देश सहित अन्य कदमों की जानकारी शीर्ष अदालत को दी हालांकि, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, यह सब हवा में है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए क्या किया गया है। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से (शेष पृष्ठ 9)



बिहार में बाढ़ का खतरा
मुंबई व हिमाचल में भारी
बारिश का अनुमान
पीएनएस। मुंबई/पटना/शिमला

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को बिहार, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और अगले 24 घंटों में बिहार के 13 जिलों में कम से मध्यम 'आकस्मिक बाढ़ का खतरा' होने की चेतावनी दी है। आईएमडी ने मुंबई और महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसका आने वाले दिनों में काफी असर होने की उम्मीद है। अनियमित मानसून के हालिया रुझान के बाद, मुंबई में व्यापक बारिश की आशंका है, खासकर कोकण क्षेत्र में, जहां आज भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, उत्तर-मध्य महाराष्ट्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, और इसके प्रभाव के कारण, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और अधिक (शेष पृष्ठ 9)

भाजपा का दामाद, दलाल पर सवाल कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया

हरियाणा चुनाव

पायनियर समाचार सेवा। रेवाड़ी/नई दिल्ली।

चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्डा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टी पर फिर से हमला बोला। हरियाणा में कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मोदी ने हाल ही में हरियाणा में अपने प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा था। वाड्डा ने लगातार किसी भी तरह के गलत काम के आरोपों से इनकार किया है और भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
मोदी के शब्दों को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने से पहले राज्य में 'डीलर, दलाल और दामाद' राज करते थे। उन्होंने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि क्या उन्हें एमएसपी का फूल फॉर्म पता है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा में भाजपा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद कर रही है। लोकसभा चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा कड़ी चुनौती पेश किए जाने के बाद, भाजपा ने जानना चाहा कि यदि पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वाड्डा को कौन रोकेगा। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हरियाणा भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा



किया कि राज्य में चुनाव 'हरियाणा के लाल' और गांधी परिवार के 'दलाल' के बीच की लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने वाड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी की तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने का मन बना लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि एक मामले में वाड्डा की कंपनी ने कथित तौर पर किसानों की 3.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की और तत्कालीन हुड्डा सरकार ने भूमि

उपयोग बदल दिया, जिससे उन्हें खरीद मूल्य से चार गुना अधिक कीमत पर जमीन बेचकर भारी मुनाफा कमाने का मौका मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अन्य मामले में, राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी करने और फिर वाड्डा से जुड़े एक बिल्डर द्वारा उनकी जमीन खरीदने के बाद उसे गैर-अधिसूचित करने के बाद किसानों ने अपनी जमीन को संकट में बेच दिया। राहुल ने अपनी ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सरल बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए छूटों व्यवसायों के लिए बैंकिंग प्रणाली खोलने की आवश्यकता पर बल दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (शेष पृष्ठ 9)

कानपुर टेस्ट मैच में बांग्लादेशी प्रशंसक से बदसलूकी का आरोप

पीएनएस। कानपुर

शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच देखने आए एक बांग्लादेशी प्रशंसक को स्टेडियम के अंदर कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट के बाद अस्पताल ले जाया गया। 'टाइगर रॉबी' नाम से मशहूर इस प्रशंसक ने बाघ की पोशाक पहनी हुई थी - बाघ बांग्लादेश क्रिकेट टीम का प्रतीक है - और ग्रीन पार्क स्टेडियम की सी ब्लाक बालकनी में खड़ा था, जहां यह घटना हुई।



सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो क्लिप के अनुसार, प्रशंसक ने इशारों से संकेत दिया कि उसकी पीठ के निचले हिस्से पर मुक्का मारा गया है। हालांकि, कानपुर पुलिस ने इस आरोप से साफ इनकार किया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसके बयान की जांच की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हरीश चंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी प्रशंसक को डिहाइड्रेशन की समस्या थी और उसे अस्पताल ले जाया गया और अब वह ठीक है। अधिकारी ने कहा, जब वह एक कान्टेबल से मिला तो बांग्लादेशी प्रशंसक सांस लेने के लिए हांफ रहा था और उससे बात करने से पहले ही बेहोश हो गया, लेकिन अब वह ठीक है। घटना से संबंधित अन्य विवरण अभी पता नहीं चल पाए हैं।
यह घटना ग्रीन पार्क के पास दक्षिणपंथी समूहों के विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है, जिसमें प्रदर्शनकारी टेस्ट मैच को रद्द करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच के मद्देनजर इलाके को सुरक्षा बढ़ा दी है। कई दक्षिणपंथी समूहों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सद्भावना चौहान पर विरोध प्रदर्शन किया, जो ग्रीन (शेष पृष्ठ 9)



धमाकों से दहला बेरुत, इजराइल के निशाने पर हिजबुल्ला मुख्यालय

पीटीआई। बेरुत

इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेरुत में हिजबुल्ला के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने टेलीविजन पर यह घोषणा की। बेरुत में हुए विस्फोट के बाद आसमान में नारंगी और काले रंग के धुएं का गुबार छा गया। यह हमला ऐसे दिन किया गया, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है।
इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि लेबनान में इस सप्ताह इजराइल के हमलों में करीब 700 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने लेबनान पर यह कहते

हुए हमले तेज कर दिए हैं कि वह हिजबुल्ला की सैन्य क्षमताओं और उसके वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बना रहा है। शीर्ष इजराइली अधिकारियों ने धमकी दी है कि यदि हिजबुल्ला की ओर से गोलीबारी जारी रही, तो वह लेबनान में भी गाजा जैसे विध्वंस को दोहराएगा। इससे पहले फॉर माइग्रेशन ने बृहस्पतिवार को अनुमान व्यक्त किया कि हमास के पक्ष में उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला द्वारा रॉकेट दागना शुरू किए जाने के बाद से लेबनान में 200,000 से अधिक लोग (शेष पृष्ठ 9)

जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। बेंगलूर

लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की। बेंगलूर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोट द्वारा सिद्धरमैया के खिलाफ जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। सिद्धरमैया पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी बी एम पार्वती को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप हैं। पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित अपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता सहेमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3)



(जो मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने की शक्ति देता है) के तहत जांच करने और 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत कार्य करते हुए, क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधीक्षक, कर्नाटक लोकायुक्त, मैसूर को मामला दर्ज करने, जांच करने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आज से 3 महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

जाता है। इसमें धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र की सजा), 166 (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण), 426 (शरारत के लिए सजा), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 340 (गलत तरीके से कारावास), 351 (हमला) और भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों को सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 9 और 13 तथा बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 3, 53 और 54 तथा कर्नाटक भूमि हड़पने निषेध अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4 के तहत दंडनीय अपराधों को भी सूचीबद्ध किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य के नाम एफआईआर में हैं।



नई दिल्ली में शुक्रवार को जीत दर्ज करने के बाद सुदृष्ट सिंह तंवर (बीच में) अन्य भाजपा पार्षदों के साथ। फोटो रंजन डिग्री

भाजपा ने जीती एमसीडी की अहम सीट, आप ने दिखाए तलख तेवर

राजेश कुमार। नई दिल्ली

नाटकीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुंदर सिंह ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट जीत ली है। यह नगर निकाय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस चुनाव परिणाम के साथ ही अब पैनल में भाजपा के 18 में से 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि सत्तारूढ़ आप के पास केवल आठ हैं। सिंह को 115 वोट मिले, जबकि पार्टी पार्षदों की अनुपस्थिति में आप की उम्मीदवार निर्मला कुमारी को

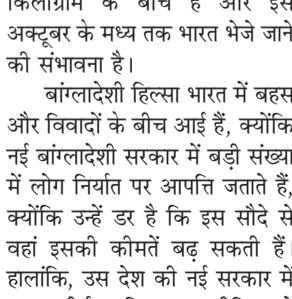
कोई वोट नहीं मिला। सिंह सदन की ओर से स्थायी समिति में छठे सदस्य के रूप में चुने गए हैं। एमसीडी स्थायी समिति की अंतिम सीट के लिए चुनाव तब हुए थे, जब भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के इस साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद यह दल खाली हो गया था। आठ पार्षदों वाली कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया। इस बीच, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी और कमलजीत सहरावत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति (शेष पृष्ठ 9)

दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेशी हिल्सा की खेप कोलकाता पहुंची

सौरग सेनगुप्ता। कोलकाता

बांगाल में बहुप्रतीक्षित 'सिल्वर क्रॉप' जैसा कि वे इसे कहते हैं, आखिरकार आ ही गई है। बहुप्रतीक्षित पद्म हिल्सा या शक्तिशाली पद्मा नदी की हिल्सा मछली, शायद दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मछली, आखिरकार कोलकातावासियों के व्यंजनों की शोभा बढ़ाने के लिए आ ही गई है।
बांगाली भद्रलोक के लिए बहुत खुशी की बात है कि शुक्रवार को लगभग 50 टन पद्म हिल्सा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मछली के पास स्थित थोक बाजार में पहुंची। यह 2,420 टन हिल्सा की पहली खेप है, जिसका वजन 800 ग्राम से लेकर लगभग 2

किलोग्राम के बीच है और इसे अक्टूबर के मध्य तक भारत भेजे जाने की संभावना है।
बांग्लादेशी हिल्सा भारत में बहस और विवादों के बीच आई है, क्योंकि नई बांग्लादेशी सरकार में बड़ी संख्या में लोग निर्यात पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस सौदे से वहां इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, उस देश की नई सरकार में एक शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ ने प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए मना लिया कि 'केवल भारतीय ही अपनी राष्ट्रीय मछली के लिए सबसे अच्छी कीमत दे सकते हैं।' यह सच है कि हिल्सा का मुंह में पानी लाने वाला स्वाद वही है, लेकिन पिछले कुछ



फाइल फोटो

वर्षों में इस पर कूटनीति बदलती रही है। पिछली श्रेष्ठ हसीना सरकार की तरह इस बेहतरीन मछली की खेप दोस्ती के तौर पर भारत आई थी।



फाइल फोटो

लेकिन इस बार सीमा के इस तरफ के एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त राजनयिक का कहना है कि यह 'अर्थव्यवस्था की खुराक' के साथ भी आई है।

बांग्लादेश से हिल्सा के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, 2012 से 2018 के बीच इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, हालांकि, बांग्लादेश ने सद्भावना और सांस्कृतिक कूटनीति के संकेत के रूप में हाल के वर्षों में दुर्गा पूजा के लिए विशेष अपवाद बनाए हैं।
दक्षिण कोलकाता दुर्गा पूजा समिति के एक आयोजक ने कहा, भारत के अन्य भागों के विपरीत बांगाल में मछली देवी को चढ़ाई जाने वाली वस्तु है और इसलिए 'हिल्सा दुर्गा को चढ़ाई जाएगी, जिनकी पूजा माता के अलावा पर आने वाली बेटों के रूप में भी की जाती है।' वे कहते

हैं कि पद्म हिल्सा सभी मछलियों की नूरजहाँ (महारानी) है। इसकी चांदी जैसी चमक के लिए नहीं बल्कि इसकी मादक गंध के लिए। इतना अधिक कि पकाए जाने पर पद्म हिल्सा की सुगंध कई घरों की दूरी पर रहने वाले पड़ोसी को भी पागल कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी बांगाल के पूर्ववर्ती जमींदार एक-दूसरे को हिल्सा खेप लूटने के लिए देशी लुटेरों को नियुक्त करते थे। किंवदंती है कि दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक हिल्सा के लालच में आ गए थे। अगर कहानियाँ पर विश्वास किया जाए, तो तुगलक ने जब इस मछली को चखा था, तब वह पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित था। इसके

अनोखे स्वाद और सुगंध से मंत्रमुग्ध होकर, वह कई दिनों तक इसे खाता रहा, जब तक कि वह अपनी भूख से पागल नहीं हो गया।
थोक बाजार में यह मछली हिल्सा की सुगंध कई घरों की दूरी पर रहने वाले पड़ोसी को भी पागल कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी बांगाल के पूर्ववर्ती जमींदार एक-दूसरे को हिल्सा खेप लूटने के लिए देशी लुटेरों को नियुक्त करते थे। किंवदंती है कि दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक हिल्सा के लालच में आ गए थे। अगर कहानियाँ पर विश्वास किया जाए, तो तुगलक ने जब इस मछली को चखा था, तब वह पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित था। इसके

हवाई अड्डा से फिल्म सिटी तक एलआरटी को मंजूरी

दो से तीन महीनों में परियोजना पर कार्य शुरू होगा, लाइट ट्रांजिट रेल 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी

पर्यायनियर समाचार सेवा। नोएडा

योगी सरकार ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से फिल्म सिटी तक लाइट ट्रांजिट रेल (एलआरटी) के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसे केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय को भेज दिया गया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले लोगों को यात्रा सुगम बनाने के लिए नमो भारत और मेट्रो लाइन के ट्रेक पर अब लाइट ट्रांजिट रेल (एलआरटी) भी दौड़ेगी। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी से हवाई अड्डा तक पूर्व प्रस्तावित फांड टेक्सी की जगह एलआरटी का टैक्सील होगा। करीब 14 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर एलआरटी संचालन के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसका प्रस्ताव भारत सरकार के केंद्रीय



प्रतीकात्मक फोटो

शहरी आवासन मंत्रालय को भेज दिया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दो-तीन महीनों में परियोजना पर कार्य शुरू हो जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ईडव) की बृहस्पतिवार को हुई बोर्ड बैठक में चैयरमैन अनिल सागर के समक्ष हवाई अड्डा से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा

वेस्ट और नोएडा को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर प्रस्तुति दी गई। इसमें बताया गया कि दो चरणों में प्रस्तावित, गाजियाबाद से हवाई अड्डा के बीच ट्रेक का निर्माण अब एक साथ किया जाएगा। पूर्व योजना के अनुसार, पहले चरण में गाजियाबाद के सिद्धार्थनगर से इकोटेक-6 तक 39.39 किलोमीटर

लंबा ट्रेक और दूसरे चरण में इकोटेक-6 से हवाई अड्डा तक 32.90 किलोमीटर लंबा ट्रेक बनाया था। पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रेक पर नमो भारत 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर तय करेगी।

अधिकारी ने बताया कि परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार 20-20 फीसदी का अंशदान करेंगी। इसके निर्माण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) लागत का 60 फीसदी खर्च करेगा। एनसीआरटीसी की अस्पष्टताओं पर धनराशि की व्यवस्था गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (नायल) करेगा।

यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि एक ही

ट्रेक पर नमो भारत, मेट्रो और एलआरटी संचालन के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके लिए 14.6 किलोमीटर का अलग ट्रेक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लाइट ट्रांजिट रेल 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सिंह ने बताया कि हर मेट्रो के बीच सेवा का अंतराल 3.5 मिनट, रैपिड रेल के बीच यह अंतराल सात मिनट और एलआरटी के लिए सेवा का अंतराल आठ मिनट रहेगा। उन्होंने बताया कि परियोजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

वहीं गुरुवार को रैपिड रेल सह मेट्रो परियोजना के लिए धन आवंटित किया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यौडव) ने गुरुवार को अपनी बोर्ड बैठक के बाद कहा कि उसने रैपिड रेल सह मेट्रो परियोजना के विकास के लिए धन आवंटित किया है जो दिल्ली को जेवर

में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी, जो अगले अप्रैल तक चालू हो जाएगी। इसके अलावा, बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में सेक्टर ओमेगा-प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित अपनी 74वां बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी। रैपिड रेल नोएडा एयरपोर्ट और गाजियाबाद आरआरटीएस के बीच चलेगी जो एक छोर पर दिल्ली और दूसरे छोर पर मेट्रो को जोड़ेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो चलेगी। नोएडा एयरपोर्ट और सेक्टर 21 के बीच 14 किलोमीटर के रूट पर एलआरटी चलाई जाएगी, जहां फिल्म सिटी विकसित की जा रही है, सिंह ने कहा। 72.44 किलोमीटर के कॉरिडोर में से 71.5 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.29 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा।



नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया।

डीएम ने मिड-डे मील खाकर परखी गुणवत्ता

नोएडा। स्कूलों में मिड-डे मील समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने रायपुर में सेक्टर-126 स्थित कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ सभी कक्षाओं का दौरा कर पढ़ाई तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने किचन में जाकर मिड-डे मील की व्यवस्था देखी तथा स्वयं खाना खाकर गुणवत्ता को परखा। बता दें कि सरकार की मिड-डे मील को लेकर कुछ स्थानों से खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत स्कूलों में जाकर निरीक्षण के का अभियान शुरू किया है। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

आईएमएस में हैकथॉन का आयोजन

नोएडा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस) नोएडा में इंटरनल हैकथॉन का आयोजन हुआ। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। एमसीए एवं बीसीए के छात्रों के लिए आयोजित हैकथॉन के दौरान कुल 15 टीम ने हिस्सा लिया। प्रौ. कार्यक्रम के दौरान बतौर निर्णायक मंडल आईएमएस के महानिदेशक प्रो.(डॉ.) विकास धवन, टीसीएस के डेवलपर रितिका चंडोक एवं प्रो. अजय कुमार गुप्ता ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को टीम ने वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लिकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सुरक्षा जैसे विषय पर तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुती दी। हैकथॉन की शुरुआत करते हुए आईएमएस के महानिदेशक प्रो.(डॉ.) विकास धवन ने कहा कि इनोवेशन एवं तकनीक बदलते समय की मांग है।

मदरसा टीचर की गर्दन काटकर भागने की फुटेज आई

गाजियाबाद। गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र स्थित मदरसे में टीचर पर आरी से हुए हमले का सीसीटीवी सामने आ गया है। इस फुटेज में छात्र को आरी लेकर अंदर घुसते हुए और फिर हमला करके करीब 7 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने देखा गया है। टीचर के पिता ने इस पूरे केसे को अलग ही कहानी सुनाई है। आरोप है कि सैलरी को लेकर टीचर और प्रिंसिपल का विवाद चल रहा है। इस विवाद में ही प्रिंसिपल और उसके भाई ने छात्र को उसका कर हमला कराया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके जमानत शुरू कर दी है। गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव ल्योडी सात बिसवा में मदरसा है।

गाजियाबाद में धर्मांतरण कराने वाला गैंग पकड़ा

पर्यायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

मोदीनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा करने का दावा किया है। चार आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। चार आरोपियों को इसी गैंग का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराता था।

इसके बदले गैंग के लोगों को कई जगहों से फांड़िज हो रही थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद डीसीपी ने इस गैंग द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराए जाने की बात कही है। डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दी। इसमें जेट के बेटे आशु सहित

तीन लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोग ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं और पैसा न करने पर धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ लिया है। इनकी पहचान आशु, पोलस मसीह, पास्टर रासी बलिहार और छठु कुमार शाह के रूप में हुई है। पूछताछ में आशु ने बताया- पिता की मौत के बाद हम लोग नोएडा के सलारपुर गांव में जाकर रहने लगे। वहां हमने ईसाई धर्म अपना लिया। अब हम लोग अपनी चाची के परिवार पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। डीसीपी ने बताया- पोलस मसीह इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड हैं।

वलती कार पर स्टंट, पुलिस ने कारा 26 हजार का चालान

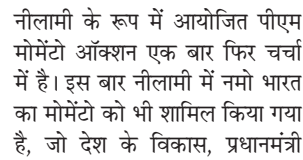
नोएडा। नोएडा में चलती कार पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर 26 हजार रुपए का चालान लगाया है। पुलिस ने लोगों से अपनी की इस तरह से वीडियो न बनाए। ये खतरनाक है।

हादसा हो सकता है। ये पूरा वीडियो 10 सेकेंड का है। वीडियो में छह युवक दिख रहे हैं। जिसमें दो युवक कार के बोनट पर बैठे हैं। बाकी चार युवक कार के दोनों ओर बाइक से चल रहे हैं। इनके हाथों में पिस्टल नुमा हथियार हैं। जिसे ये हवा में लहरा रहे हैं। सामने से इसका वीडियो शूट किया गया। इसकी रील बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य साइटों पर अपलोड किया गया।

रैपिड रेल नमो भारत का मोमेंटो भी होगा नीलाम

● 2 अक्टूबर तक लगाए ऑनलाइन बोली

पर्यायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद



दिल्ली से मेट्रो तक चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का मोमेंटो भी अब नीलाम किया जाएगा। इसे पीएम मोमेंटो ऑक्शन में शामिल किया गया है। यह मोमेंटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैपिड रेल के पहले चरण साहिबाबाद से दुहाई तक 20 अक्टूबर 2023 को शुभारंभ के समय दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर प्राप्त किए गए उपहारों और स्मृति-चिन्हों को

का मकसद न केवल संग्रहणीय वस्तुओं को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि इससे प्राप्त राशि को राष्ट्रीय धरोहरों, खासकर नमामि गंगे परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की पवित्र नदियों की सफाई और संरक्षण में सहयोग करना है।

इसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की भी झलक देखने को मिलती है। पीएम मोदी को दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह नीलामी भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य उन उपहारों और मोमेंटो को नीलाम करना है जो प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न अवसरों पर मिले हैं। नीलामी

सलारपुर गांव में पत्नी की गला दबाकर हत्या

पर्यायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के सलारपुर गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव कमरे के बेड पर छोड़कर फरार हो गया। एक दिन तक शव बेड पर ही पड़ा रहा। बदबू आने पर पड़ोस के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला।

पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। महिला का पति मिस्त्री का काम करता है। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि सलारपुर में मिस्त्री आनंद अपनी पत्नी के साथ किराए के एक कमरे में रहता था। किसी बात को लेकर

दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आनंद ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को गांव के लाला उर्फ रणवीर का फोन चौकी पर गया। उसने बताया कि कमरे से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला। अंदर महिला का शव का बेड पर पड़ा था। आनंद फरार था।

उन्होंने बताया कि आनंद छतरपुर गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्टर-39 पुलिस की टीम गठित की गई है। छतरपुर के लिए रवाना हो गई है। महिला के गले पर दबावे के निशान हैं। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य लिए हैं जांच पड़ताल का जा रही है।

दो महीने पहले हुई हत्या का खुलासा

गाजियाबाद। मोदीनगर के मुरादनगर क्षेत्र में हुई शादाब की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

यहां के पाटुलाइन मार्ग पर एनटीपीसी के गोदाम के पास स्थित खड्डर में एक अगस्त को शादाब की शव पुलिस को मिला था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म के मामले में दी गई जमानत तोड़ने की धमकी और गाली देने पर सगे भाईयों ने ही शादाब की गला दबाकर हत्या की थी।

ICICI Bank
शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 23, शाल टावर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहातक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सार्वजनिक सूचना:
बिल्डर निरस्तकरण
आपके ध्यान में लाया जाता है कि हमलावा यादव/अनशील कुमार (उपचारकर्ता/ओ) ने फ्लैट नं. 604, 6वीं मंजिल, टॉवर बी2, अंगन, गांव हरिसर्का, सेक्टर-88ए/89ए, गुरुग्राम में स्थित, सुविधा समझौता नं. LBDE0L0005031996 के अंतर्गत यह बिल्डर सुविधा का काम उठाया है। उच्चारकर्ता/ओ समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार बिल्डर को संचिदागत राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। बैंक उसकी सूचना कर्जदार को पत्र विनांकित 19 जुन, 2024 के माध्यम से दे चुका है, जिसमें सूचित किया गया है कि एलएनडिब्लेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त समर्पित का आबंटन निरस्त कर दिया है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि बिल्डर के साथ यह मामला इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के भीतर सुझाव दें। कृपया यह भी ध्यान दे कि उक्त समर्पित के आबंटन निरस्त करने के पश्चात आईसीआईसीआई बैंक बिल्डर द्वारा किए गए किसी भी अन्य आवंटन के लिए बाध्य नहीं रहेगा/या उतरदायी नहीं होगा।
दिनांक: सितंबर 27, 2024
स्थान: दिल्ली/एनसीआर
कृते आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड हस्ता/—

PUBLIC NOTICE
This is to inform to public at large that my client Sh. Kishan Chand Pawar S/o Late Ram Lal R/o E-383, J.J Colony, Madli Pur, New Delhi-110063 have severed all relationship from his son Vijay Kumar @ Vicky and his wife Smt. Neha Panwar and their children Ranveer Panwar @ Tanish, 11 years and Parnavee Panwar, aged about 6 years and disowned and debarred them from all their moveable and immovable properties as they have become disobedient and they are out of control of my above client and my client have nothing to do with them. My client shall not be responsible for their acts, deeds. If any person deals with them then they will be doing that at his/her own risk, cost and consequences.
Sandeep Kushwaha (Advocate)
OFF: 1097556, Gali No 5 & 6, 2nd Floor, Sat Nagar, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.

ICICI Bank
शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शाल टावर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहातक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आरक्षणों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को मांग सूचना निम्नलिखित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्त की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करेंगे।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसमाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे बतलित समर्पित का अधिभोग प्रवर्तन का प्रयोग करके कोर्ट से हस्तगत किया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसमाधारण को सूचित कि संव्यवहार नहीं करने हेतु संवर्धित किया जाता है तथा समर्पित के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
क्र. सं. कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ साक्षात्ता का क्र. समर्पित का विवरण/ सांकेतिक कर्जकी की तिथि तिमांड नोटिस की तिथि/ तिमांड नोटिस से राशि (₹.) शाखा का नाम
1. विप्लव कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मकान नं. 2545, बागीची, सुपुष्प, सर बाजार, दिल्ली-110006, 2. श्याम लाल राविका कुमार 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहाड़नगर, दिल्ली-110085 और मेरठ में शंभू मकानिका मूल, दुबान नं. 2736, सरत थाना रोड, दिल्ली-110006, 3. क्र. 20200112672527 (क्या रिपोर्ट) की कुल राशि प्राय: 13.04.2023 के बाद अर्जित मधिय के ब्याज और मुल्य के साथ) 4. शंभूकान्त 38.00 वर्ग मी. दिल्ली-110055, 5. अशोक कुमार पुत्र सुधीर सिंह, 142 सी, एलएडव्ही फ्लैट, मोहिया खान पहा

गुरुग्राम में घर से मतदान प्रक्रिया शुरू

● चारों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन विभाग की टीमों ने डलवाए वोट

● मतदान की गोपनीयता मंग ना हो: डीसी निशांत यादव

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम



गुरुग्राम में घर से मतदान करती बुजुर्ग महिला।

जिला में शुक्रवार से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होम वोटिंग शुरू हुई। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने होम वोटिंग का निरीक्षण किया। सभी टीमों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए।

गुडगांव, बादशाहपुर, सोहना व पटौदी विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को फार्म-12डी जमा करवाने वाले 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग व चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के उनके घर पर ही वोट डलवाए गए। होम वोटिंग के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि मतदान की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। डीसी ने के सेक्टर चार में स्वयं होम वोटिंग का निरीक्षण किया। उनके समक्ष सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका 93 वर्षीय शकुंतला शारदा ने मतदान किया। वोट डालने के बाद बुजुर्ग महिला बेहद प्रसन्न नजर आ रही थी और उन्होंने इस सुविधा के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीमार अवस्था के कारण वह मतदान केंद्र तक नहीं जा सकती थी। निर्वाचन विभाग ने वृद्ध नागरिकों को यह सुविधा प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला में 1173

मतदाताओं के घर पर वोट डलवाए जाएंगे, जो कि आज से शुरू हो गए हैं। आज जो व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएंगे, उनके रविवार 29 सितंबर को वोट डलवाए जाएंगे। चारों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में गठित की गई टीमों होम वोटिंग करवा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए यह सेवा शुरू की हुई है। आयोग का मानना है कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए।

होम वोटिंग करवा रही टीमों को डीसी ने निर्देश दिए हैं कि घर पर वोटिंग कपाउंड इस तरह से बनाया जाए कि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। प्रशासन की ओर से इस कार्य की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। केवल मतदाता को ही बैलेट पेपर पर निशान लगाकर वोट डालने की अनुमति होगी। बाहर का कोई व्यक्ति इस कार्य में सहयोग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार या उनके द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट भी होम वोटिंग को दूर से देख सकते हैं। वे मतदाता के करीब नहीं जा सकेंगे और ना ही उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे।

मतदाता सूचना पर्वी वितरण कार्य शुरू

● वोटर इनफार्मेशन स्लिप में मिलेगी वोट संबंधी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

आगामी पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के चलते बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्वी यानी वोटर इनफार्मेशन स्लिप का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला के सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों पटौदी, गुडगांव, बादशाहपुर व सोहना में व्यापक स्तर पर चुनाव की तैयारी जारी है। चुनाव आयोग द्वारा इस बार अनूठी पहल की गई है। जिससे मतदाताओं में मतदान के प्रति रूझान पैदा हो।

संबंधित बूथों के बीएलओ द्वारा वोटर इनफार्मेशन स्लिप वितरण

किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाताओं को स्वीप गतिविधियों के जरिए जागरूक किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को मतदान संबंधी सूचना के लिए मतदाता सूचना पर्वी में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान केंद्र, मतदान की तिथि, समय आदि से संबंधित जानकारी क्यूआर कोड के साथ शामिल है। उन्होंने बताया कि मतदान से पांच दिन पूर्व यानि 30 सितंबर तक जिलेभर के सभी 1504 बूथों के बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्वी वितरण कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने सभी बीएलओ का आह्वान किया कि निर्धारित समय पर मतदाताओं को वोटर इनफार्मेशन स्लिप वितरण करें, ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन यानि पांच अक्टूबर को वोट करने के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए।

पीट कर हत्या के खिलाफ कानून लाने का वादा

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

● कांग्रेस प्रत्याशी ने दिलाया भरोसा

नूंह विधानसभा सीट से इस बार भी चुनाव लड़ रहे अफताब अहमद ने गुराक्षा के नाम पर किसी की पीट-पीट कर हत्या कर देने के खिलाफ कानून लाने और पिछले साल जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच कयने जैसे वादे किए हैं।

निवर्तमान हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता अहमद ने बताया कि नूंह में सांप्रदायिक हिंसा होने से

पहले ही चेतावनियां दी गई थीं और उन्होंने प्रशासन को पहले ही इस बात से अवगत करा दिया था लेकिन उन्होंने इसे होने दिया। अहमद ने कहा, पिछले वर्ष नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा का कारण भाजपा द्वारा गौराक्षकों के वेश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना था, जिससे यहां

भय का माहौल पैदा हुआ और ये उग्र हो गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेवाड़ी में एक बैठक करने में व्यस्त थे। दोनों पक्षों के असामाजिक तत्वों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद पूरे मार्ग के लिए केवल 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। आज तक हम मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों, हिंसा के कारणों और हिंसा से निपटने के उनके तरीके का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच की जाए।

प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने किया पुस्तक का विमोचन

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्षता प्रो. तरविंदर जीत कौर और गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुना नगर की असिस्टेंट प्रोफेसर रूही ग्रेवाल द्वारा लिखित पुस्तक 'डिस्टिपलडेमिया सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिस्टिकल्स एज फूड कंपोनेंट्स' का आज विमोचन किया। सचदेवा ने पुस्तक की लेखिका तरविंदर जीत कौर और श्रीमती रूही ग्रेवाल को बधाई भी दी।

आरक्षण खत्म करना चाहती हैं भाजपा-कांग्रेस: मायावती

● कहा- बसपा इनैलो की सरकार बनने पर अजय चौटाला होंगे सीएम

● वहीं, एक डिप्टी सीएम दलित व दूसरा पिछड़े वर्ग या अपर कास्ट से बनाया जाएगा

पायनियर समाचार सेवा। पलवल



कहा कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनाने पर अजय चौटाला सीएम होंगे, जबकि एक डिप्टी सीएम दलित समाज व दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़े वर्ग या अपर कास्ट से बनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद पांडाल तालियों की गडगड़ाहट से गुंज उठा। इस दौरान मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार व आईएनडीआई गठबंधन को घेरने का काम किया।

मायावती ने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी कोर्ट की आड़ में आरक्षण को

तरफ से इस बारे में कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर केंद्र की बीजेपी सरकार चाहते और विपक्ष साथ दे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विधेयक लाकर इस फैसले को निष्प्रभावी किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन ने संविधान व आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में वोट तो ले लिए, लेकिन कोर्ट के फैसले पर चुप है। राहुल गांधी विदेश में आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वार्गीकरण से अधिकार राज्य सरकार को दिया है। प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य सरकार इस फैसले को लटका कर रख सकती है, जब तक केंद्र व विपक्ष संसद में संवैधानिक विधेयक लाकर इसमें बदलाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि आरक्षण को बचाने के लिए इन वर्गों को आरक्षण विरोधी पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। इन पार्टियों ने नौकरियों का ठेका भी पूंजीपतियों को दे दिया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती।

कमजोर करने व खत्म करने के प्रयास में लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एससी व एसटी के आरक्षण में वार्गीकरण व क्रोमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है। अगर आरक्षण के मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार को नियत साफ होती, तो सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसके लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आती, ताकि आरक्षण कमजोर न हो। विपक्ष में बैठा आईएनडीआई गठबंधन की

हार नजदीक देख कांग्रेस प्रत्याशी बौखलाए: गौरव

● चुनाव आयोग में उनके खिलाफ 300 से अधिक की झूठी शिकायतें

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

पलवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम का गांव चिरवाड़ी में ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने गौरव गौतम का 21 लाख रुपये की माला और चांदी का मुकुट भेंट करने के साथ-साथ फूलों की वर्षा और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया।

इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल पर तंज कसते हुए कहा

कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसलिए उनके समर्थक अब तक चुनाव आयोग में उनकी 300 से अधिक झूठी शिकायतें कर चुके हैं। क्योंकि उन्हें भी अब यह पता चल गया गया कि पलवल की जनता ने अबकी बार यह ठान लिया है कि पलवल जिले को डर और आतंक से मुक्त बनाना है। आज कांग्रेस प्रत्याशी यह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह एक हिंदू हैं और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए पलवल के लोगों को भी अपने साथ ले जाएंगे। जबकि नूंह में हुए दंगों के दौरान मेवात में दिए गए बयानों पर अभी तक उन्होंने अपनी कोई सफाई नहीं दी है। गौरव गौतम ने कहा कि उन्होंने केभी धर्म और जात-पात की राजनीति नहीं की है।

सबसे सुंदर शहरों में शुमार होगा बल्लभगढ़: शर्मा

● भाजपा प्रत्याशी बोले, लगभग 18 महीने में पूरा हो जाएगा शहर को जाम मुक्त करने का मेरा सपना

पायनियर समाचार सेवा। बल्लभगढ़

आगामी एक अक्टूबर को फरीदाबाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बड़-चढ़कर भाग लेगी और दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोषण को सुनेगी।

भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान बल्लभगढ़ की जनता को न्योता देते हुए कहा कि यह फरीदाबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद आ रहे हैं। अनाज मंडी के पास नागर निवास पर चौधरी जगराम नागर द्वारा



आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने मौके पर उपस्थित जनसमूह से भाजपा के लिए वोट की अपील की। मूलचंद शर्मा ने कहा विकास के मामले में बल्लभगढ़ विधानसभा 2027 तक हरियाणा की सबसे सुंदर विधानसभाओं में शुमार होगी।

भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ को जाम मुक्त करने का मेरा सपना लगभग 18 महीने में पूरा हो जाएगा, मोहना रोड पर बनाए जाने वाले

बागी होकर चुनाव लड़ रहे नेताओं को कांग्रेस ने छह साल के लिए निकाला

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बागी होकर चुनाव लड़ रहे 13 नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। इससे पहले अंबाला छावनी में एक बागी प्रत्याशी चित्रा सरवारा को भी बाहर किया जा चुका है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने अधिकारिक प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जा चुका है। इसके बावजूद पूर्व समय के दौरान टिकट का दावा करने वाले कई नेता अभी भी मैदान में उठे हुए हैं। बार-बार चेताने के बावजूद उन्होंने न तो नाम वापस लिया है न ही प्रचार बंद कर रहे हैं। जिसके चलते पार्टी हाईकमान को स्वीकृति के बाद छह साल के लिए 13 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर किया जा रहा है।

‘फसल खरीद में किसान को न हो परेशानी’

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में बाजरे की खरीद प्रबंधन बारे संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडी में फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध समय रहते किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला में 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू की जाएगी।

डीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक में पिछले सीजन में हुई आवत व इस बार मंडियों ने आने वाली फसल की अनुमानित आवत की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि खरीद के दौरान जिला में स्थापित मंडियों में किसानों के समक्ष जैसे बिजली-पानी, शौचालय व टोकन आदि सहित अन्य किसी प्रकार की

● फसल खरीद के दौरान किसानों के समक्ष किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए: डीसी

● जिला में एक अक्टूबर से शुरू होगी बाजरे की खरीद

दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीसी ने कहा कि निर्धारित शैड्यूल के अनुरूप ही किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर आएंगे।

फसल खरीद के बाद मंडी से फसल का उठान भी साथ-साथ होना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद के दौरान पर्याप्त संख्या में बारदाना कम है तो उसके बारे में उच्चाधिकारियों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि फसल के उठान के लिए

पर्याप्त संख्या में ट्रंसपोर्टेशन भी होना चाहिए। इसी प्रकार से उचित गोदाम की व्यवस्था हो। आढतियों के पास तिरपाल, झरना, वजन, पर्याप्त लेबर और बारदाना सीलने के लिए समुचित संख्या में सिलाई मशीन होनी चाहिए। डीसी ने निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यूरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल ही सरकारी खरीद पर मंडियों में होगी। फसल की खरीदारी टोकन के हिसाब से होगी।

कृषि उप निदेशक अनिल तंत्र ने डीसी को बताया कि जिला में 21 हजार से अधिक किसानों ने करीब 84 हजार एकड़ क्षेत्र में बाजरे की फसल का मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि बाजरे की खरीद एमएसपी यानी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। बैंक में मार्किट कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि मंडियों में फसलों की आवत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है।

एचएसएससी ने मांगी परिणाम घोषित करने की अनुमति

● मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि हाईकोर्ट ने 31 मई को आदेश जारी कर 6 माह में मर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए थे आदेश

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

राज्यसभा सांसद कांग्रेसी नेता जयराम नरेश को शिकायत पर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को परीक्षा विस्तृत परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है।

आयोग के सचिव ने इस बारे में मुख्य सचिव को हिसा देते हुए पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने 21

अगस्त, 2024 और 30 अगस्त, 2024 के पत्र के माध्यम से आयोग को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले साइटिफिक ऑफिसर सी (सिस्टम इंजीनियर) को भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञान नंबर 12, 5666 पुलिस कांस्टेबल को भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञान नंबर 14 और सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा) का परिणाम घोषित नहीं करना है।

उन्होंने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2023 में दायर की गई एलपीए (अपील) नंबर 1037 व अन्य संबंधित मामलों में हाईकोर्ट ने 31 मई, 2024 को आदेश

दिया था कि उपरोक्त पदों के लिए प्रथम प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए जिसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया परीक्षा परिणाम के लंबित होने के कारण वर्ष 2022 से लंबित है लेकिन परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक के कारण

31 मई को हाईकोर्ट ने यह दिए थे आदेश

- प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंड (सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया) के लिए 5 मई, 2022 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना को अमान्य घोषित किया जाता है और इसके आधार पर दिए गए बॉनस मार्क्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।
- सीईटी का परिणाम जो 10 जनवरी, 2023 व 25 जुलाई, 2023 को जारी किए गए परिणाम को अमान्य घोषित किया जाता है। सीईटी मार्क्स के आधार पर फ्रेश मैरिट लिस्ट बनाई जाए।
- राज्य के विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करें।
- पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए, आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाएं।

अब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का खतरा बना हुआ है जिसके कारण आयोग के खिलाफ कोई आदेश जारी हो सकता है। अपनी उपरोक्त मांग के लिए, आयोग ने अदालत की अवमानना को याचिका के बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए

आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि था कि किसी भी अन्य अंधोरिटी द्वारा जारी आचार संहिता को हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को आचार संहिता के बावजूद लागू करना जरूरी है।

संक्षिप्त समाचार



श्री चित्रगुप्त स्कूल में स्वीप कार्यक्रम में भाग लेते शिक्षक व कर्मचारी।

श्री चित्रगुप्त स्कूल में आयोजित किया स्वीप कार्यक्रम

गुरुग्राम। मतदाताओं को 5 अक्टूबर के दिन विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए स्वीप टीमों आम जन के बीच जाकर उन्हें मतदान की प्रेरणा दे रही हैं। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि शुक्रवार को गांव टीकली के श्री चित्रगुप्त स्कूल में सिविल डिफेंस की टीम ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ के सदस्यों को मतदान का महत्व बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ को मतदान की शपथ दिलवाई गई। मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम में स्कूल निदेशक सुरेश कुमार, संगीता, रंजनदास इत्यादि मौजूद रहे। सिविल डिफेंस के समन्वयक मोहित ने बताया कि टीकली के साथ अखलीमपुर, पलडु, गैरतपुर बास में स्वीप की और भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

अनेक पंचायतों के सरपंच व सदस्य भाजपा में शामिल लाडवा। कुरुक्षेत्र जिले लाडवा हलके में भाजपा प्रत्याशी एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान चौधरी जितेंद्र सिंह सरपंच खैरा की अग्रुवाई में जिला परिषद, ब्लॉक समिति व विभिन्न पंचायतों के सरपंचों और मेंबरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने वाले सभी जिला परिषद मेंबरों, ब्लॉक समिति मेंबरों व विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों का सीएम नायब सैनी ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि लाडवा हलके में भाजपा में लोगों की आस्था बढ़ रही है और काफी संख्या में पदाधिकारियों और सम्मानित व्यक्तियों के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा का कुनवा बढ़ा है।

हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचेगी भाजपा: मनोहर लाल

● पंजाबी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। कैथल



कैथल के ग्रेस होटल में पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यातिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लालातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले ही पता है कि वे कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने कई पार्टियों से गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि वोट डालने से पहले सोचना कि कौन सी पार्टी आपको व आपके बच्चों की हैतरीशी है। आपको स्पष्ट हो जाएगी कि भाजपा से बेहतर कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि कैथल सहित पूरे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का काम करें।

एलिवेटेड पुल पर काम आचार संहिता लागने से पहले ही शुरू हो चुका है उन्होंने कहा कि पुल के बनने के बाद बल्लभगढ़ मथुरा रोड स्थित मेट्रो स्टेशन बस अड्डा से 2 की दूरी मात्र 64 और 65 के अलावा सेक्टर 2 के भी मंत्री 5 मिनट में तय होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमने जो कहा था वह हमने किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 76 साल के इतिहास में मेरा बल्लभगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने का सपना पूरा हो चुका है।

नेताओं से वोट का हिसाब मांग रही हरियाणा की जनता

भाजपा-कांग्रेस के कई प्रत्याशियों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा में भी हो चुका है हंगामा, लोग कर रहे मुद्दे की बात

● जवाब सुनकर खुलेआम हार व जीत के दावे कर रही जनता

शिखा शर्मा | चंडीगढ़

हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश स्तर पर अभी तक जहां केवल नौकरियों व दलित उपीड़न का मुद्दा छाया हुआ है वहीं हलका स्तर पर लोग अब प्रत्याशियों से हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक करोड़ों के उम्मेदवारों जैसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने प्रत्याशियों से उनके पिछले कार्यकाल के दौरान वादों पर सार्वजनिक सभाओं के दौरान हिसाब मांगा और हिसाब नहीं देने पर प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा।

जनता इस बार भाजपा व कांग्रेस को निशाना बना रही है। जींद जिले की नरवाना सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी चुनाव प्रचार के लिए गांव कर्मगढ़ गए थे। इस दौरान यहां मौजूद लोगों ने उनसे सवाल किए और जवाब मांगा। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से कहा कि किसान आंदोलन में उनके समर्थन में उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की। पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इससे पहले गांव भिखेवाला में भी युवाओं ने बेदी को घेरेकर नौकरियों पर जवाब मांगा। प्रत्याशी समर्थकों तथा ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्का भी हुई।



भाजपा सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक से दस साल का हिसाब मांगते लोग।



हिसार में मनोहर लाल की जनसभा के दौरान सवाल करता एक युवक।

नायब सरकार में राज्य मंत्री रहे नांगल चौधरी विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहीर बाहुल्य कोरियावास गांव में विरोध हुआ। यहां कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। युवक प्रदीप ने कहा कि आपने किया क्या है, फिर वोट क्यों दें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भतियों को रोक कर बैठ गए। जिसके कारण युवा परेशान हैं। युवक ने कहा कि दस साल जो बवाल महेंद्रगढ़ के थे वहीं

आज हैं। यहां मंत्री को माइक नहीं दिया गया। फतेहाबाद के रतिया से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को गांव भूथन कला में किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों ने दुग्गल पर सांसद होते हुए उनकी मांगों को अनदेखा का आरोप लगाया। टोहाना विधानसभा के गांव चंद्रवाल में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री देवेन्द्र बबली की जनसभा में किसान जमकर हंगामा कर चुके हैं।



अरविंद शर्मा को भी कुछ इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ा।



युवक को जनसभा से बाहर ले जाते पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर का सुरक्षाकर्मी।

किसानों ने गांव की समस्याओं और पुरानी मांगों पर बबली से रिपोर्ट मांगी। ग्रामीणों ने पुराने मांग पत्र भी दिखाए जो बबली को विकास एवं पंचायत मंत्री रहते हुए दिए गए थे। अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गांव स्याणा पूर्व विधायक सीता राम को घेरेकर उनके गांव की गलियों के निर्माण नहीं होने पर सवाल पूछे गए। गांव चंद्रवाल में तो बबली को अपनी घोषणाएं पूरी नहीं होने पर माफी तक मांगी पड़ी। झुंजर में भाजपा के

प्रत्याशी कसान बिरधाना जब विकास की बात कर रहे थे तो गांव लडखन में लोग उन्हें जनसभा से उठाकर ले गए और गांव की उन गलियों में उतार दिया जहां बारिश का पानी जमा था। विपक्षी दल कांग्रेस में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राजू का सैनी समाज और सैनी न्याय संघर्ष समिति द्वारा एक ट्रस्ट के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है। कालका से पूर्व कांग्रेस विधायक एवं वर्तमान

कांग्रेस की गारंटियों से नहीं बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था: गहलोत



● गारंटी लागू होने से हरियाणा बनेगा मॉडल

● ओपीएस व 25 लाख तक मुफ्त इलाज योजना राजस्थान में हो चुकी लागू

पायनियर समाचार सेवा | चंडीगढ़

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को जो गारंटियां दी हैं उनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

चंडीगढ़ में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह गारंटियां बड़े संच विचार के बाद और वित्त विशेषज्ञों से राय लेने के बाद दी गई हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की नीति रही है कि जनता से बातचीत करके, सब की राय जान कर और आम आदमी की आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि यह गारंटियां जब लागू हो जाएंगी तो हरियाणा एक मॉडल स्टेट बन कर उभरेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि यह कहना बिलकुल सही नहीं है कि कांग्रेस ने केवल चुनाव जीतने के लिए हरियाणा की जनता के साथ बड़े बड़े वादे किए हैं। राजस्थान के अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जो गारंटियां हरियाणा की जनता को दी गई हैं उनमें से बहुत सारी वे राजस्थान में लागू कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना राजस्थान में बड़ी सफलता के साथ लागू की गई है। इसी प्रकार ओपीएस को भी राजस्थान ने दोबारा लागू कर दिया है। ऐसे में हरियाणा में भी सभी वादों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। गहलोत ने कहा कि हरियाणा देश में पहला राज्य होने वाला है जहां बुढ़ाया, विधवा और दिव्यांग पेंशन 6000 रुपए प्रति माह होने जा रही है। तीन से युक्ति विजली फ्री देने की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि कांग्रेस जनता के बीच मुफ्त रेविडियां बांटने का काम कर रही है। गहलोत ने कहा कि आम आदमी को राहत पहुंचाना और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना सरकार की जिम्मेवारी है।

‘मंडियों में एमएसपी से 500 रुपये सस्ती बिक रही धान, किसान परेशान’

● इंद्री में राकेश कंबोज के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा

● भाजपा छोड़कर आए कण्ठदिव ने कहा, जीटी रोड से साफ हो जाएगी बीजेपी

पायनियर समाचार सेवा | चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर किसानों को एमएसपी से वंचित रखना चाहती है।



कई दिनों से किसानों का धान मंडियों में पहुंच रही है। ऊपर से बारिश का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन सरकार धान की खरीद शुरू करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान एमएसपी से 500 रुपए कम में अपनी फसल को मजबूर हैं। हर फसली सीजन में किसानों के साथ बीजेपी द्वारा यही खिलवाड़ किया जाता है।

ही कंबोज को अस्पताल से छुटी मिली थी। आज की रैली में वह ड्रिप लगाकर पहुंचे हुए थे। हुड्डा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप मेरे कहने पर इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज को विजयी बनकर भेजना और मैं आपके कहने पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। जनसभा को पूर्व मंत्री कर्ण देव कंबोज ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान समेत हर वर्ग तानाशाही व बेलागम भाजपा सरकार से नाराज है। जीटी रोड बेल्ट से इस बार भाजपा पूरी तरह साफ होने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की नीतियां पूरी तरह किसान विरोधी हैं। आज किसान खुद बताते हैं कि कांग्रेस के राज में, जौरी गई जहाज में और अब बीजेपी की राज

में 'जौरी गई ब्याज में'। क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को फसलों के ऊंचे रेट मिलते थे। लेकिन बीजेपी कार्यकाल में किसानों को एमएसपी से भी कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार ने गन्ने के भाव में रिकॉर्डतोड़ 193 की बढ़ोतरी की थी। कांग्रेस ने 117 रुपये से बढ़ाकर गन्ने का रेट 310 रुपये किया था, यानी 165% की बढ़ोतरी। लेकिन बीजेपी ने 10 साल के भीतर गन्ने के रेट में बमुरिकल 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने जनता को परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और मेरी फसल-मेरा ब्योरा जैसे पोर्टलों के घोटालों में उलझाकर रख दिया है। जबकि किसान ने जो फसल उगाई है, उसे उसकी एमएसपी मिलनी ही चाहिए।

आयुष्मान भारत के डिटी सीईओ के घर से मिले एक करोड़ रुपये, आरोपी रिमांड पर

● एसीबी की टीम ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन

पायनियर समाचार सेवा | चंडीगढ़

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की करनाल टीम द्वारा गुरुवार को रिश्त के मामले में पकड़े गए आरोपी आयुष्मान भारत के डिटी सीईओ डा. रवि विमल को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बीती रात एसीबी की टीम ने डॉक्टर के पंचकुला के अमरावती स्थित फ्लैट से एक करोड़ 2 लाख रुपये बरामद किए हैं। सरकारी प्रकाश ने

और इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। डॉ.रवि विमल पंचकुला में आयुष्मान भारत योजना के डिटी सीईओ के पद पर कार्यरत था। एसीबी की टीम को करनाल के एक निजी अस्पताल के संचालक से शिकायत प्राप्त हुई कि आरोपी डॉ. रवि विमल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध उसके अस्पताल का सम्पत्तिन रह करने के बदले में 10 लाख रुपये मांग रहा है जिसमें से 5 लाख रुपये देने की बात तय हुई जिसे लेते हुए एसीबी ने आरोपी को रों हाथों गिरफ्तार कर लिया।

हरियाणा में पीआरटी की लिखित परीक्षा आज

चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की पहल करते हुए आयोग द्वारा पीआरटी (प्राइमरी टैचर) की परीक्षा आज आयोजित की जाएगी, इसमें लगभग 45000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। चौहान ने बताया कि टीजीटी परीक्षा के लिए अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में केंद्र होंगे। उन्होंने बताया कि 160 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी शाम को परीक्षा देंगे। चौहान ने बताया कि अंबाला में आयोग के सदस्य सुभाष चंद्र, करनाल में साधु राम जाखड़ और भूपेंद्र सिंह चौहान, कुरुक्षेत्र में कपिल अत्रेया व अमर सिंह रहेंगे। इसके अलावा आयोग के सचिव विनय कुमार व विशेष कार्यकारी अधिकारी शंभू लिखित परीक्षा के सभी प्रबंधों की सुपरविजन करेंगे।

सार्वजनिक सूचना
मेरी सुप्रीम कोर्टी शरीर नैशनल पब्लिक सर्विस (एनपीएस) द्वारा निम्नलिखित सूचना A-30/10 के अंतर्गत 82 वें चक्र में 51.83 वर्ग मीटर, अक्षांश 27.9, लंबाई 10.5 मीटर का प्लॉट नं. 1, माता हरिदास, मौजूद, गरीब, गरीब, इलाहाबाद दिल्ली-110053 की आवादी में निहित है, जो श्री सुधीर कुमार शर्मा के नाम पर है। यह प्लॉट नं. 1, माता हरिदास, मौजूद, गरीब, गरीब, इलाहाबाद दिल्ली-110053 के तहत निम्नलिखित सूचना 2024/23/7349 SR-IV A दिल्ली के तहत निम्नलिखित है। उपरोक्त प्लॉट के डेड लाइन के तहत निम्नलिखित के पास से हस्तांतरण किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्ति/व्यक्ति/व्यक्ति के पास उपरोक्त प्लॉट के संबंध में कोई दावा/भूतबिनाश, अधिकार, कोई भी दावा है, तो उसे दस्तावेजी रूपों के साथ इस प्लॉट के अद्यतन की तिथि से 7 दिनों के भीतर पीएनडीए अधिकांश के माध्यम से अधीनस्थ/एडवोकेट विशाल मेहनत ई-713, कडकड़वा कोर्ट, दिल्ली-110092 के पास पर सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावे, उपस्थित या आगे की कानून का विचार नहीं किया जाएगा। एडवोकेट विशाल मेहनत, ई-713, कडकड़वा कोर्ट, दिल्ली-110092, मोबाइल-9811215181

पशु आहार निर्माण शाला, रुद्रपुर
किसा नर्षणण रोड, रुद्रपुर (कथन तिहार नगर) फोन नं. 6694-24552 ई-मेल: ananchal@rediffmail.com
फाई: 18848/निर्माण/2024-25
दिनांक 27-09-2024

सार्वजनिक सूचना
पुनः अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या- 06(1-4)/CFP/2024-25, Date- 27/09/2024
निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा Two Bid System के अंतर्गत पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में निर्माता फर्म से 1-काम्येक फीड ब्लाक (भूसा मेली प्लेन) 100% गैरू का भूसा, 2-फिल्टेड लिक्विड कैल्शियम ब्लाक पाटी मैयूकैल्शियम फर्म से क्रय करने, व निर्माण/आपूर्तिकर्ता फर्म से 3-डीडीजीओएस (साईस बेस), क्रय करने हेतु तथा 4-विभिन्न प्रजाति (सागीन, पीपल, मलवरी, शीशम, सेमल, पीपल, कटहल तथा आम) के पशुओं की बिक्री हेतु दिनांक 06/10/2024 के सांघ 05.00 बजे तक पुनः अल्पकालिक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 07/10/2024 की प्रातः 11.00 बजे शुरूसीडीओएस कार्यालय मंगल पड़ाव हद्दानी में खोली जायेगी।

क्र.सं	विवरण	कुल मात्रा	घरोर धराराशि	निविदा शुल्क
01	काम्येक फीड ब्लाक (भूसा मेली प्लेन) 100%	10000 कुन्तल	₹ 1,75,000	₹ 4,720
02	फिल्टेड लिक्विड कैल्शियम (05 किग्रा० पैक)	60000 किग्रा०	₹ 1,44,000	₹ 4,720
03	डीडीजीओएस (साईस बेस)	1750 कुन्तल	₹ 1,01,100	₹ 4,720
04	विभिन्न प्रजाति (सागीन, पीपल मलवरी, शीशम, सेमल, पीपल, कटहल तथा आम) के पशुओं की बिक्री	97 नग	₹ 15,000	₹ 590

नोट- निविदा की शर्त तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतीकरण का तरीका-
निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार फी.एस.टी. सहित, निविदा प्रपत्र Online Internet की वेबसाइट <https://uktenders.gov.in> पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी हेतु समय-समय पर वेबसाइट का अद्यतन किया जाना आवश्यक है। निविदा वेबसाइट पर दिनांक 28.09.2024 से उपलब्ध रहेगी। सामान्य प्रबंधक

PUBLIC NOTICE
To be known to all, Vrinda Upadhyaya W/o Shri Yogesh Upadhyaya R/o Flat No. 209 F, Pocket 1, Mayur Vihar, Phase 1, Delhi-110091, is the owner of Property Flat No. 209 F, Second Floor, Pocket 1, Mayur Vihar, Phase 1, Delhi-110091, has have applied for certified copy & conversion from leasehold to freehold in DDA. The original Possession Letter, of the above said Flat has been lost. An F.I.R./NCR/LR No. 2158391/2024 dated 27/09/2024 to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch, Delhi.
Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 991054977 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (LAB) Housing or Director (LAB) Housing, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
Vrinda Upadhyaya

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the General Public on behalf of our client that Mrs. Rashmi Gupta is claiming to be owner of Property bearing No. B-44 (Old No. 1450/11-E), area measuring 80 sq. yds. out of Kharsa No. 63277, situated in the area of Village Sikdarpur, in the abadi of Gali No. 04, Jyoti Colony, Ilaqa Shahdara, Delhi-110032; vide GPA, ATS & Will dated 08.12.2015 executed by Mr. Rakesh Kumar & Mr. Madan Mohan. All persons are hereby informed that above mentioned owner wants to sell the said property to a person who wants to obtain a loan from our client against the said property. If anybody has any objection upon the ownership of above owner over the said property, its sale/ mortgage/ litigation or any other objections, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days of the present.
Kumar & Associates (Advocates & Consultants)
206, Plot No. 23, Shivaji Vihar, Moh Nagar, N. Delhi-15
Ph: 91-11-21527-28, legal@kumarandassociates.com

NOTICE
Locker Hired by MONIKA JUNEJA having address at B-4-1 SECTOR-7 ROHINI New Delhi-110085 Delhi India with Branch Janakpuri B-3/63, Ground Floor, Janakpuri, New Delhi - 110058 remains un-operated from last 90 days.

NOTICE
Locker Hired by EKTA ARORA & SANDEEP ARORA having address at 69-1 2ND FLOOR AVSHOK NAGAR NEW DELHI DELHI-110018 Delhi India with B-3/63, Ground Floor, Janakpuri, New Delhi - 110058 remains un-operated from last 90 days.

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Harpreet Singh S/o, Gurdev Singh, R/o. M-133-136, Raghubir Nagar, Tagore Garden, Delhi - 110027 that My Wife's name Pawan Kaur Wrongly Written in my minor daughter Brahamleen Kaur (Date Of Birth 19/04/2021) school's documents but her correct name is Pawan Kumari. PD(789)C

LOST & FOUND

I, Mr. Siddharath Bhardwaj S/o Mr. S.P Bhardwaj has to inform that I have misplaced the Original Share Certificate of C-102, Mayurdhwaj Apartments, Plot No.60, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092 having Membership No.73 and is not traceable by my best efforts. PD(800)A

INDIAN BANK
साखा: लाजपुर नगर साखा, ए-13, प्रथम तल, डीडीई कॉम्प्लेक्स, टिफिन कॉलोनी, दिल्ली-110024
ईमेल: L512@indianbank.co.in
दिनांक: 24.09.2024
(अल्पकालिक सूचना)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, उपोह्यव्यवस्था में वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रकाशित का एक्ट नं. 54) के अधीन इंडियन बैंक लाजपुर नगर साखा (साखा कोड 4363) दिल्ली का कर्तव्य प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार मैसर्स महाशक्ति एंटरप्राइजेज प्रा.प. मुकेश कुमार पुत्र श्री रूप चंद गारंटर (1) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रूप चंद उधारकर्ता को एक मांग सूचना दिनांक 14.05.2024 को जारी की गई थी जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 1,00,56,884.00 (एक करोड़ छप्पन हजार आठ सौ बीसवीं भाग) और दिनांक 14.05.2024 से भुगतान की तिथि तब ब्याज, आकस्मिक प्रभार, लागत प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो गये हैं इसलिए एतद्वारा कर्जदार/गारंटर/बचककर्ता तथा सर्वसम्पन्न को सूचित किया जाता है कि उपोह्यव्यवस्था में संश्लेषण/आवृत्तियों का कर्तव्य प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदात शक्तियों के प्रयोग में नीचे उल्लिखित संश्लेषण पर दिनांक 24.09.2024 को कर्तव्य ले लिया है। कर्जदार का ब्याज एक्ट की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिवर्तितियों के मुक्त करने हेतु, उपलब्ध सामग्री सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा सामान्य रूप से जनसम्पन्न को एतद्वारा उक्त संश्लेषण के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संश्लेषण के साथ कोई भी लेन देन इंडियन बैंक, लाजपुर नगर साखा के प्रभार वाले बकाया राशि रु. 1,00,56,884.00 (एक करोड़ छप्पन हजार आठ सौ बीसवीं भाग) दिनांक 13.05.2024 तक ब्याज राशि और भविष्य का ब्याज, आकस्मिक चर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अल्पकालिक सूचना का विवरण
सम्पत्ति मकान नं. 89, क्षेत्रफल 320 वर्ग गज (कुवर्डी परिया 870 वर्ग फीट) 4 कमरे, शौचालय और बाथरूम के साथ बिजली और पानी का कनेक्शन, गांव नाहरपुर रुपा, तटसील और जिला मुद्रगांव में स्थित, पंजीकरण सं. 5917, पुस्तक सं. 01, खंड सं. 9753, प्लॉट सं. 140 में दिनांक 02/06/2010 को बिक्री बिलेख द्वारा पंजीकृत
दिनांक: 24.09.2024 | स्थान: मुद्रगांव हस्ता/ (प्रतिभूत अधिकारी) इंडियन बैंक

ICICI Bank | शाखा कार्यालय: आई सी आई बैंक लि. 4/10, माइथी टावर, बोमनल्लो होस्पर मेन रोड बेंगलूर-560068

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूचन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। ऋण(ओं) को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसे तामील नहीं किया गया है और इसलिए इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/उधारकर्ता का नाम और पता (कृपया साक्षात् करें)	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	नोटिस भेजने की तिथि/नोटिस की तिथि तब बकाया	एनपीए की तिथि
1.	दीपजित दास/पैयू दास/टॉवर ए फ्लैट नं. 103 सेक्टर-6 देवकीदेवी सेक्टर 103 तलाबबाद 53 मुद्रगांव मुद्रगांव-122006/ LBBNG0006984610/ LBBNG00069812239	अनुसूची 'क' संघित (जिसका फीट ऊपर उल्लेख किया गया है) परिवर्तित मूचि का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका संश्लेषण सं. 42/1, खाता सं. 285/189/1 के साथ, 1 एकड़ और 10 गुंटा (कुल विस्तारित 1 एकड़ और 18 गुंटा की सीमा में से) जोकि चिककासने गांव, कासाबा होबली, देवनहल्ली तालुक, बेंगलूर ग्रामीण जिला और आधिकारिक ज्ञान एएलएन(एस) क्र. सं. 82/2003-04 दिनांक 12 अप्रैल 2004 के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया गया और निम्नानुसार चौकी: पूर्व में - श्री नारायणप्पा और श्रीमती मुनीरथम्मा की भूमि, पश्चिम में - गूडू टोपू की भूमि, उत्तर में - सन्नी अम्मानिकेरे वैनल, दक्षिण में - डोड्डासन्ने रोड, अनुसूची 'सी' 0.892% अविभाजित हिस्सा 486 वर्ग फीट के बराबर, अनुसूची-ए संघित में अधिकार और हित, अनुसूची 'सी' अपार्टमेंट प्लेट नं. ए-001 जिसमें संघित आईडी नं. 150300201901020357, जो ए-ब्लॉक के भूतल में, लगभग 1045 वर्ग फीट या 97.2 वर्ग मीटर, जिसमें योजना के अनुसार 2 बेडरूम हैं, जिसमें विट्टाफाइड प्लोरिंग दी गई है, एक कार पार्किंग के साथ, बहुमंजिला इमारत में शामिल सामान्य क्षेत्रों जैसे मार्ग, लॉबी, सीढ़ी में आनुपातिक हिस्सेदारी शामिल, "रकाई गोल्ड" के नाम से ज्ञात जीवनकीर्ति कमांडर्स एरर्यूयू अनुसूची 'क' संघित पर निर्मित, पश्चिम में - मार्ग और प्लेट नं.-ए011, पूर्व में - झाड़व ये, उत्तर में - बी-ब्लॉक, दक्षिण में - प्लेट नं. ए002	26.08.2024 64,70,237.34/-	04-07-2024
2.	श्रुति सिंह/ 3605 हिलोय नजिल सेक्टर 23 मुद्रगांव-122017/ LBBNG0006906589/ LBBNG0006885586	अनुसूची 'क' संघित (जिसका फीट ऊपर उल्लेख किया गया है) परिवर्तित मूचि का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका संश्लेषण सं. 42/1, खाता सं. 285/189/1 के साथ, 1 एकड़ और 10 गुंटा (कुल विस्तारित 1 एकड़ और 18 गुंटा की सीमा में से) जोकि चिककासने गांव, कासाबा होबली, देवनहल्ली तालुक, बेंगलूर ग्रामीण जिला और आधिकारिक ज्ञान एएलएन(एस) क्र. सं. 82/2003-04 दिनांक 12 अप्रैल 2004 के अनुसार आवासीय उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया गया और निम्नानुसार चौकी: पूर्व में - श्री नारायणप्पा और श्रीमती मुनीरथम्मा की भूमि, पश्चिम में - गूडू टोपू की भूमि, उत्तर में - सन्नी अम्मानिकेरे वैनल, दक्षिण में - डोड्डासन्ने रोड, अनुसूची-ख संघित (श्रुति में अविभाजित हिस्सा) 0.89% अविभाजित हिस्सा 483 वर्ग फीट के बराबर, ऊपर उल्लिखित अनुसूची-ए संघित में अधिकार और हित, दूसरी मंजिल पर अपार्टमेंट सं. ए-204 के निर्माण का अधिकार "रकाईगोल्ड जीवनकीर्ति कमांडर्स एरर्यूयू" नामक बिस्किंग कॉम्प्लेक्स के 1040 वर्ग फीट के सुपर बिल्ड अप एरिया के भाग हेतु रु. 54,94,100 (रुपये बीघन लाख बीघन हजार एक सौ मात्र) के विचारविमल हेतु, अनुसूची - सी - संघित अपार्टमेंट नं. ए-204 रकाईगोल्ड जीवनकीर्ति कमांडर्स एरर्यूयू की इमारत की दूसरी मंजिल पर, जिसका ई-खाता नंबर-150300201901021338 अपार्टमेंट 1040 वर्ग फीट सुपर बिल्ड-अप एरिया एक कर्बड कार पार्क और चौकी: पूर्व में - सेटवैक एरिया और झाड़व ये, पश्चिम में - रास्ता और ए-209 उत्तर में - ए-203 दक्षिण में - ए-205	27.08.2024 59,12,396.32/-	04-07-2024

ये कदम नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए उदाहरण हैं। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या गारंटर(ओं) (जिसका लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।
दिनांक: सितंबर 27, 2024
स्थान: दिल्ली/एनसीआर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी
कृपया आई सी आई सी आई बैंक लि.

सिद्धरमैया पर संकट

घोटाले के आरोप

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपने पूर्व कार्यकाल में कथित भूमि घोटाले के कारण राजनीतिक व विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष अदालत द्वारा मैसूरु लोकयुक्त पुलिस को कथित 'मूडा' घोटाले में उनकी संलिप्तता की जांच करने के आदेश के बाद सिद्धरमैया पर संकट गहरा गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी है जिसमें राज्यपाल द्वारा जांच की सहमति को चुनौती दी गई थी। सिद्धरमैया पर 2013-2018 के अपने पूर्व कार्यकाल में कथित भूमि घोटाले का आरोप है। अब इस मामले के तूल पकड़ने के कारण वे विवाद में घिरे हैं। इन आरोपों का संबंध बैंगलुरु में महत्वपूर्ण जमीन का 'डिनोटीफिकेशन' से है जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए निजी डेवलपर्स को दिया गया था। इस घटनाक्रम से न केवल राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, बल्कि इससे कांग्रेस सरकार के स्थायित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं जो पहले से ही अंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस मामले ने विपक्षी दलों और एक्टिविस्टों के आरोपों को उजागर कर दिया है जिन्होंने सिद्धरमैया पर अपने पद का दुरुपयोग कर निजी लोगों के पक्ष में भूमि के डिनोटीफिकेशन का आरोप लगाया था। आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। डिनोटीफिकेशन आमतौर से उन मामलों में किया जाता है जहां सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि की जरूरत न हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह निर्णय निहित स्वार्थों से प्रभावित था।



इस जांच का उद्देश्य सिद्धरमैया की भूमिका और इस बात का पता लगाना है कि क्या उन्होंने कानूनी दायरे में रह कर काम किया। हालांकि, जांच अभी शुरूआती चरण में है, पर इसके राजनीतिक प्रभाव दिखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी-भाजपा द्वारा गंभीर जांच और यहां तक कि उनके इस्तीफे की मांग करने से सिद्धरमैया पर दबाव बढ़ रहा है। आरोपों के जवाब में सिद्धरमैया ने किसी गलत काम का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने जांच को 'राजनीति से प्रेरित', अपनी छवि खराब करने तथा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास बताया है। अपने बचाव में सिद्धरमैया का कहना है कि भूमि का डिनोटीफिकेशन कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया गया था और संबंधित अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ही मामले कई पार्टियों के अनेक राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। उनका संकेत है कि यह विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को परेशान करने का आम राजनीतिक तरीका है और इसका संबंध केवल उनके प्रशासन से नहीं है। लेकिन यदि जांच गति पकड़ती है और उनके खिलाफ ठोस सबूत सामने आते हैं तो पार्टी के भीतर तथा जनता की नजरों में उनकी छवि निश्चित रूप से खराब होगी। कर्नाटक में मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा इस भूमि घोटाले का लाभ उठा कर सिद्धरमैया की निष्ठा और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएगी। यदि मामला अदालतों में गया तथा न्यायिक निगरानी की मांग हुई तो भाजपा की जवाबदेही की मांग से लंबी राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है। कर्नाटक जैसे राज्य में भ्रष्टाचार की कोई आशंका सिद्धरमैया की सार्वजनिक छवि ध्वस्त कर सकती है क्योंकि यहां चुनावी मुकाबला कठोर का होता है। सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शिता और विकास के वादों पर सत्ता में आई थी। ऐसे में यह मामला तूल पकड़ने तथा और ज्यादा सटीक सबूत सामने आने पर सिद्धरमैया का संकट और गहरा सकता है जिसमें वे अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

एकसाथ चुनाव की ओर बढ़ता भारत

भारत में एकसाथ चुनाव कराने की भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए इसका सफल क्रियान्वयन अनिश्चित बना हुआ है।



कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत में एकसाथ चुनाव कराने की भूमिका तैयार हो रही है। इसके लिए 'एक देश, एक चुनाव' का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए इसका सफल क्रियान्वयन अनिश्चित बना हुआ है। 'एक देश, एक चुनाव' का विचार संसदीय व आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने पिछले सप्ताह इसे आगे बढ़ाने का निर्णय भी कर लिया है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और संसद के आगामी सत्र में यह विधेयक पेश करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित की थी जिसकी रिपोर्ट और संस्तुतियों को अब स्वीकार कर लिया गया है।

हालांकि, इस अवधारणा पर अतीत में भी बहुत बार बहस हो चुकी है, पर इस पर कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी थी। वर्तमान समय में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-भाजपा की सरकार लंबे समय से चुनाव सुधारों के पक्ष में रही है और अब वह चुनाव व्यवस्था में परिवर्तनों को गति देने का प्रयास कर रही है। 'एक देश, एक चुनाव' इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक परिवर्तनकारी चुनाव सुधार हो सकता है। अतीत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा बाद में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एकसाथ चुनाव कराने का विचार सामने रखा था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस विचार को खारिज कर दिया था।

वर्तमान समय में भाजपा द्वारा यह प्रस्ताव आगे बढ़ाने का समय बहुत अच्छा है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस समय रखा जब वे पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री के रूप में लगातार अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुके थे। भाजपा पिछले दो दशक से अधिक समय से इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की पैरवी



कर रही है। हालांकि, यह विचार तार्किक और कारगर दिखता है, पर इसे क्रियान्वित करने पर अनेक सवाल भी उठते रहे हैं। इस संबंध में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत ऐसे सुधार के लिए तैयार है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास आवश्यक दो-तिहाई बहुमत है जिसके द्वारा वे संसद में यह विधेयक पेश कर संविधान संशोधन कराने में सफल होंगे? इसके साथ ही अनेक अन्य सवाल भी हैं जिनके जवाब की आवश्यकता है। सर्वाधिक प्राथमिक और सबसे जरूरी यही तथ्य है कि इस विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत होने पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा अपने दम पर सदन में बहुमत से 40 सीटें पीछे रह गई और वह जनता दल जनतांत्रिक गठबंधन-राज्य का हिस्सा थी और उन्होंने एकसाथ मिल कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा की वर्तमान गणित को देखते हुए भाजपा को इन दलों के साथ ही अन्य मैत्रीपूर्ण दलों का समर्थन प्राप्त करना होगा। भाजपा 'एक देश एक चुनाव' के माध्यम से चुनाव

प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन इसीलिए करना चाहती है क्योंकि उसके विचार से ऐसा करने से बार-बार चुनाव कराने से मुक्ति मिल जाएगी। एकसाथ चुनाव होने से सरकार तथा राजनीतिक दलों का चुनावों पर होने वाला खर्च भी घटेगा। लेकिन इन सबके बावजूद अधिकांश विपक्षी दलों ने एकसाथ चुनाव का विचार खारिज कर दिया है। इस विचार को अस्वीकृत करने वाले दलों में कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस तथा क्षेत्रीय व अन्य छोटी पार्टियां शामिल हैं। उन्होंने इसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया है कि इससे सत्तारूढ़ दल को 'राजनीतिक बदला' लेने का अवसर मिल जाएगा। उनको यह आशंका भी है कि इसे भाजपा को लाभ होगा।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस मुद्दे पर विचार कर इस बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों की राय ली और इसके बाद सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। कोविंद समिति के समक्ष उपस्थित हुई 32 जनतांत्रिक गठबंधन-राज्य का हिस्सा थी और उन्होंने एकसाथ मिल कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा की वर्तमान गणित को देखते हुए भाजपा को इन दलों के साथ ही अन्य मैत्रीपूर्ण दलों का समर्थन प्राप्त करना होगा। भाजपा 'एक देश एक चुनाव' के माध्यम से चुनाव

होनी चाहिए जिसका सभी चुनावों में प्रयोग किया जा सके। वर्तमान समय में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान सूची में बार-बार सुधारों के साथ ही स्थानीय निकायों में मतदान सूची बनाया अलग होती है। इस संयुक्त सूची का प्रयोग कर मतदाता राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय निकाय चुनावों में वोट दे सकेंगे। इससे मतदाताओं के पंजीकरण में आने वाली कमियों को कम किया जा सकेगा। समिति ने इस संबंध में सभी पक्षों से बातचीत की योजना बनाई है।

समिति ने दो हिस्सों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। पहला चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के लिए तथा दूसरा स्थानीय निकायों के लिए होगा। ऐतिहासिक रूप से 1952 में पहले चुनाव होने के बाद से 1967 तक एकसाथ चुनाव होते थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद से स्थिति बदल गई। उन्होंने विपक्ष शासित राज्य सरकारों को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना शुरू किया जिससे स्वतंत्र चुनावों की शुरुआत हुई। इसके बाद से आज तक यही स्थिति के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना शुरू हुआ है। लेकिन 'एक देश एक चुनाव' पर विधेयक को अनेक संवैधानिक, विधिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समिति ने देश में एकसाथ चुनाव कराने के

लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन का सुझाव दिया है। ये संशोधन अनुच्छेद 83 से 172 तक होंगे। भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं है, जबकि संविधान संशोधनों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इसके साथ ही संविधान इस विषय पर मौन है कि क्या चुनाव एकसाथ होने चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संसद में उपयुक्त संख्या में सांसदों को लामबंद करना होगा। इसके साथ ही अभी 'एक देश एक चुनाव' पर राजनीतिक सहमति बनाने का काम भी बाकी है। भाजपा ने इस दिशा में विपक्षी दलों से बात करने या उनको समझाने-बुझाने का प्रयास नहीं किया है।

विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक मूड में है क्योंकि उसका विश्वास है कि एकसाथ चुनाव से भाजपा को लाभ होगा। कांग्रेस इसके विरोध में है। इसी प्रकार वामपंथी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन ने भी यह विचार अस्वीकार कर दिया है। 15 विपक्षी दलों के पास 205 सांसद हैं, जबकि मोदी को 362 मतों की आवश्यकता है। एकसाथ चुनाव के लिए विधिक ढांचा भी जरूरी है जो आवश्यक परिवर्तन कर सके। इसके साथ ही कार्यकाल के बीच में ही गिर जाने वाली राज्य सरकारों की समस्या से भी निपटना होगा। यह विचार अच्छा है और इससे पैसा भी बरबादी पर लागू लाग सकती है। इसके 10 ही हरे द साल में चुनाव से नीतिगत विकलांगता जैसी स्थिति पैदा होती है।

इसलिए विपक्ष को खारिज करने के पहले इस पर विचार करना चाहिए। यदि उनके पास कोई वैकल्पिक योजना हो तो इस पर सार्वजनिक बहस हो सकती है। कुल मिला कर मोदी इस विधान को संसद में एक राजनीतिक अंतर्गत ला रहे हैं। चाहे हारे या जीते, इससे मोदी को लाभ होगा। यदि वे जीत जाते हैं तो यह एक चुनावी वादा पूरा करना होगा। यदि विधेयक गिर जाता है तो भी वे हमेशा इसे अच्छे इरादे से लाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। भले ही यह विधेयक लाने में विफल हो, पर इस पर बहस होनी चाहिए तथा एकसाथ चुनाव का रास्ता अंततः निकाला जाना चाहिए। आखिरकार बार-बार चुनावों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च करदाताओं का पैसा है।

क्वाड का स्पष्ट दृष्टिकोण

क्वाड सम्मेलन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना है।



कुमारीदी बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाई-प्रोफाइल अमेरिका यात्रा ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का महत्व रेखांकित करते हुए अनेक प्रमुख निर्णयों के माध्यम से 21वीं शताब्दी में साझेदारी का भविष्य निर्धारित कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा रूस और यूक्रेन की उनकी यात्राओं के बाद हुई। यह बहुआयामी दृष्टिकोण उजागर करती है जहां भारत सर्वोच्च स्तर पर राजनयिक संपर्क मजबूत करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को पवित्रतम मानता है। प्रधानमंत्री मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने परस्पर मैत्रीपूर्ण ढांचा रेखांकित किया, जबकि प्रधानमंत्री ने 'ओवल आफिस' में उनके पूर्ववर्ती के

साथ राजनीतिक रोड शो किया था। यह सारी दुनिया को संकेत है कि अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों को सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त है। क्वाड नेताओं के सम्मेलन, अनिवासी भारतीयों के साथ मोदी का 'राकस्टार कंसर्ट' शैली के आयोजन तथा अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र के सीईओ के साथ बैठक ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों ने बहुत तेज गति प्राप्त कर ली है। ऐसे में पीछे देखने की किसी प्रकार की आशंका का कोई स्थान नहीं है।

क्वाड सम्मेलन की बैठकों में चीन की अदृश्य उपस्थिति रही। क्वाड सम्मेलन ने बिना नाम लिए आक्रामक तथा समुद्री अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने वाले के रूप में चीन को और संकेत किया। इसमें कहा गया, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चार प्रमुख समुद्रतटीय लोकतंत्रों के रूप में हम स्पष्ट रूप से इस परिवर्तनशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो वैश्विक सुरक्षा तथा समृद्धि का अपरिहार्य तत्व है। हम इस क्षेत्र को



अस्थिर करने वाले या किसी एकपक्षीय कार्यवाहियों का घोर विरोध करते हैं जो शक्ति या दबाव से यथास्थिति बदलने को और संकेत किया। हम क्षेत्र में ऐसे अवैध मिसाइल प्रक्षेपणों की निन्दा करते हैं जो समुद्रतटीय लोकतंत्रों के रूप में हम स्पष्ट रूप से इस परिवर्तनशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो वैश्विक सुरक्षा तथा समृद्धि का अपरिहार्य तत्व है। हम इस क्षेत्र को

देश प्रभुत्व न बनाए तथा किसी देश पर प्रभुत्व न स्थापित हो। इस क्षेत्र में सभी देश दबाव से मुक्त हों और अपना भविष्य तय करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। हम एक स्थिर व खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो मानवाधिकारों, स्वतंत्रता के सिद्धान्त, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का दृढ़ समर्थन करें

तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार धमकी या शक्ति प्रयोग न करें। असोसिएशन आफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स-आशियान, पैसिफिक आईलैंड्स फोरम-पीआईएफ तथा इंडियन ओसेन रिम असोसिएशन-आईओआरए समेत क्षेत्रीय संस्थाओं के नेतृत्व का सम्मान क्वाड के सभी प्रयासों के केन्द्र में है और यह बना रहेगा।

हालांकि, क्वाड 'नाटो' की तरह कोई रक्षा साझेदारी नहीं है, पर वैश्विक महाशक्ति चीन की उपस्थिति तथा उसके द्वारा पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनाए जाने वाली दबाव की रणनीतियों के कारण डेलावेयर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता प्रभावित थे। दिल्ली, राष्ट्रपति बाइडेन के गृह शहर डेलावेयर, सिडनी और टोकियो अंतरराष्ट्रीय समुद्रों पर गहरी नजर बनाए हुए हैं जहां चीन के अनेक उल्लंघन सामने आए हैं। नेताओं ने घोषणा की, 'आज हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल-मैत्री को घोषणा कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में हमारे साझेदारों को आईपीएमडीए तथा अन्य

क्वाड साझेदार पहलों से प्राप्त उपकरणों को अधिकतम बनाने में सहायता करेंगे।

इससे हम समुद्रों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित कर कानूनों को लागू कर सकेंगे। हम 2025 में भारत में होने वाली मैत्री कार्यशाला की ओर देख रहे हैं। इसके साथ ही क्वाड साझेदार अगले वर्ष आईपीएमडीए में नई तकनीक और डेटा को समाहित करेंगे जिससे हम इस क्षेत्र में अद्यतन क्षमता और सूचनाओं को उपलब्ध कर सकेंगे।' इस प्रकार चीन क्वाड नेताओं की प्रमुख चिन्ता बना रहेगा और इन चारों देशों को जोड़ने के लिए शक्तिशाली गोंद का काम करेगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख हित रखने वाले देश ज्यादा निकट आएंगे। अगला क्वाड सम्मेलन दिल्ली में होने की आशा है, जहां एक नया अमेरिकी राष्ट्रपति प्रमुख सामने आए हैं। नेताओं ने घोषणा की, 'आज हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल-मैत्री को घोषणा कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में हमारे साझेदारों को आईपीएमडीए तथा अन्य

आप की बात

एनआरआई कोटा

पंजाब सरकार द्वारा मेडिकल में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा रखने पर देश के प्रधान न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने इसकी जरूरत को खारिज करते हुए कहा कि इससे देश के मेधावी छात्रों के पहले भाई-भतीजावादियों को फायदा मिलेगा जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार को सही तर्क देते हुए एनआरआई कोटे की अनुमति को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सवाल है कि आखिर एनआरआई कोटा क्यों दिया जाना चाहिए? इससे एक ओर एनआरआई के रिश्तेदारों के छात्र फायदा उठाते हुए देश के प्रतिभावाण छात्रों का हक मारेंगे तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा।

दिसानायके की चुनौतियां

राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका के मतदाताओं ने श्रमिक के बेटे अनुरा कुमारा दिसानायके को चुना। जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होने की पद्धति के चलते दिसानायके 50 प्रतिशत से कम वोट पाकर भी राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे देश के इतिहास में पहली बार मतगणना के दूसरे दौर में जीते हैं। संसद में उनके मात्र तीन प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। स्पष्ट है कि दिसानायके को सत्ता की बागडोर संभालकर श्रीलंका को सुशासन देने में कदम-कदम पर विपक्ष का विरोध सहना पड़ेगा। अतीत में व्यक्त अपनी भारत-विरोधी विचारधारा के चलते उन्हें निष्पक्ष छवि बनानी होगी तथा यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वह चीन की कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे। पहले तमिल-विरोधी होने के कारण उन्हें तमिल जनता को भी विश्वास में लेना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत-चीन के बीच निष्पक्ष संतुलन बनाकर रहेंगे। विदेशी कर्ज में आकंट डूबी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाना मुश्किल होगा। जहां भारत ने उनको पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है, वहीं चीन भी उन पर डोरे डालने में लग गया है। ऐसे में देखा होगा कि आने वाले कुछ महीने में दिसानायके देश की राजनीति व अर्थनीति को क्या दिशा देते हैं।

- सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

बाल यौन अपराध

सुरक्षित कोर्ट ने सुझाव दिया है कि संसद को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण-पाक्सो कानून में संशोधन को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे कहा है कि बाल पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसके परिणामस्वरूप ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सकेगा। पीठ ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में नहीं किया जाएगा। सुरक्षित कोर्ट के निर्देशानुसार, बाल पोर्नोग्राफी देखना और उसे डाउनलोड करना यौन अपराधों से बच्चों का

आर्थिक संतुलन के प्रयास

फेडरल रिजर्व द्वारा अमेरिका में आधा प्रतिशत घटाए जाने और आगामी वर्षों में दो प्रतिशत तक घटाए जाने की संभावना व्यक्त की है। फेडरल रिजर्व के इस कदम ने दुनिया के पूंजी बजार और शेयर बाजार में उथल-पुथल मचाई है। इसके कारण भारतीय शेयर बाजार लगातार रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है। जैसे फेडरल रिजर्व के ब्याज घटाने वाले कदम के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए। डॉलर का अंतरराष्ट्रीय बाजार और बहुल गहरा प्रभाव पड़ता है और

उसी के अनुरूप विश्व की अन्य करेंसियां चलती हैं। यदि भारत में भी ब्याज दर घटाई जाती है तो इसका फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को भी दिया जाना चाहिए। हालांकि, रिजर्व बैंक मुद्रास्फूर्ति बढ़ने के ब्याज से पिछले काफी समय से भयान दरों में कटौती से बच रहा है। इससे कर्ज लेने वाले लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तथा अर्थव्यवस्था की प्रगति भी प्रभावित होती है। लेकिन दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में आर्थिक संतुलन बहुत कठिन काम है।

- विभूति बुधवार, खानरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

आतंकवाद व सिंध नदी का जल प्रवाह साथ-साथ नहीं चल सकता

● कहा, टेरिस्ट स्टेट नहीं, अब ट्रिजना स्टेट बन गया है जम्मू-कश्मीर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ जम्मू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग बचपन में गाते रहे हैं कि 'बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चिनाब नहीं।' भारत सरकार ने 1960 के सिंधु बंटवारे की समीक्षा का आदेश देते हुए दो टुक कहा है कि 'बॉटर एंड टेरिस्टिज्म डॉट फ्लो ट्रूदोर' यानी आतंकवाद और सिंध नदी का जल प्रवाह साथ-साथ नहीं चल सकता। अभी तक पाकिस्तान के हाथों में कटोरा आया है, अब वह एक-एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है।

दूसरे दिन भी जम्मू-कश्मीर के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूसरे दिन भी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के

प्रचार में पहुंचे। शुक्रवार को उन्होंने रामनगर से उम्मीदवार सुनील भारद्वाज, उधमपुर ईस्ट से प्रत्याशी रणवीर सिंह पटानिया, कठुआ से प्रत्याशी भारत भूषण, किश्तवाड़ से उम्मीदवार शगुन परिहार के लिए कमल खिलाने की अपील की।

सीएम योगी को देखने-सुनने के लिए दोनों जनसभा में जबर्दस्त भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान आज दो कारणों से परेशान है। पहला तो वह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहरा

लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा कि नए भारत में खून की नदियां नहीं बहती हैं, बल्कि यह अपनी सुरक्षा करना जानता है। सीएम योगी ने कहा कि साढ़े सात वर्ष में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी की तरह ही जम्मू-कश्मीर भी विकास का इकदर है। योगी ने कहा कि कांग्रेस, पीडीपी व नेशनल कॉंग्रेस ने धरती के स्वर्ण को मजहबी उन्माद के पाप का वेयर हाउस बनाकर जनता का शोषण किया। इन लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद, भ्रष्टाचार को पनपाया, लेकिन अब 370 व 35 ए को हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में विकास तेजी से बढ़ गया है। टेरिस्ट स्टेट से दूरिस्म स्टेट बन गया है। जम्मू-कश्मीर में देश का सबसे बड़ा और ऊंचा ब्रिज बन रहा है तो वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन भी जम्मू से दिल्ली तक शुरू हुई है। नेकों। कांग्रेस व पीडीपी ने युवाओं को तमंचा धमया था, लेकिन पीएम

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार टैबलेट देकर नौजवानों को रोजगार दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 370 बहाल करेंगे यानी यह लोग फिर से आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पुराने दौर को लाना चाहते हैं। इन्हें शांति-सौहार्द व विकास नहीं, बल्कि सत्ता चाहिए, लेकिन इन तीनों दल के लिए यहां जगह नहीं है। जनता तिकड़ी को विदा करने का संकल्प ले चुकी है। सत्ता मिलने पर कांग्रेस, नेका व पीडीपी के नेता 12 में से 8 महीने यूरोप-इंग्लैंड और तीन महीने दिल्ली रहते थे। आखिर एक महीने में जम्मू का विकास कैसे होगा।

योगी ने कहा कि कांग्रेस, नेका व पीडीपी की तिकड़ी ने यहां अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और आतंकवाद को बढ़ाया। बकरवाल, गुज्जर, दलित, वाल्मीकि समाज के लोगों को हक से वंचित कर रखा था।

चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र का व्यापक कार्याकल्प कराएगी प्रदेश सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● 53.04 करोड़ रुपए की लागत से

व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन प्रक्रिया को किया जाएगा पूरा

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने अब चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक कार्याकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम योगी की मंशा के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडी) ने मं रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। योजना के अनुसार, 53.04 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि अटल इंस्ट्रिट्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन की प्रक्रिया को पूरा करने की रूपरेखा तय की गई है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को वर्ष 1978 में स्थापित व 2006-07 में विकसित किया गया था। यह औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज-

कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से जुड़ा है और मुगलसराय रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किमी की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा, वाराणसी से इसकी दूरी करीब 30 किमी है, और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बाबतपुर, यहां से लगभग 51 किमी की दूरी पर है। यह क्षेत्र दोनों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से जुड़ा हुआ है, और अपनी बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आवागमन की दृष्टि से बहुत सुगम है। यह औद्योगिक क्षेत्र करीब 515 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 16.8 किमी का विकसित सड़क नेटवर्क और 15.8 किमी लंबा ड्रेनेज सिस्टम भी शामिल है।

अखिलेश सुर्खियां बटोरने के चक्कर में जातियों के बीच नफरत फैला रहें: भूपेन्द्र सिंह चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुर्खियां बटोरने के चक्कर में भ्रम फैलाकर जातियों के बीच वैमनस्वता और नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर कुछ भी अगर्गल पोस्ट करने से पहले सपा प्रमुख को थोड़ा रिसर्च वर्क और सोच विचार भी कर लेना चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना अखिलेश यादव को शोभा नहीं देता।



सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चार साल पहले अखबार में छपी एक खबर को अपने एक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए यूपी लोकसेवा आयोग की आरक्षण व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश

चार साल पुरानी खबर डालकर समाज में जातियों के बीच नफरत और वैमनस्वता फैला रहे हैं। बार बार हार का मुंह देखने के बाद सपा प्रमुख और उनकी टीम पूरी तरह से बीखला गई है और समाज को भ्रमित करने वाले ऐसे पोस्ट के जरिए सामाजिक समरसता को विगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख पहले भी बेवजह को पुरानी तस्वीरों को पोस्ट करके झूठ और भ्रम फैलाने की अपनी कोशिशें जगजाहिर कर चुके हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उन्होंने वाराणसी में वरुणा नदी को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, बाद में पता लगा कि वो तस्वीर उनका ही कार्यकाल की थी। अखिलेश एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं और सांसद भी, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्हें शोभा नहीं देती। इस प्रकार से सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाने की हर कोशिश का भारतीय जनता पार्टी पुर्जोर विरोध करती है।

अयोध्या के 14 गांवों में निर्माण से सेना के अभ्यास में क्या समस्या

● हाईकोर्ट ने सेना के सक्षम अधिकारी को सुनवाई में सहयोग के लिए बुलाया

विधि संवाददाता। लखनऊ

अयोध्या जनपद के कैंट क्षेत्र में सेना के अभ्यास क्षेत्र से लगे 14 गांवों की जमीनों में यदि निर्माण के लिए नक्शे सपा किए जाते हैं अथवा निर्माण की अनुमति दी जाती है, तो क्या समस्या आ सकती है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सेना से इस सवाल का जवाब मांगा है। पीठ ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव को भी हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि क्या उक्त गांवों के लिए नक्शे को संस्तुति करना संभव है और क्या इसके लिए सेना से एनओसी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

एट अयोध्या' शीर्षक से दर्ज सुओ मोटो याचिका पर दिया है। पीठ ने इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर आदेश पारित करते हुए कहा था कि बेहतर होगा कि सुनवाई के बजाय स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) याचिका दर्ज की जाए। पीठ के समक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टेशन हेडक्वार्टर, अयोध्या कैंट की ओर से 11 फरवरी 2023 को अयोध्या के जिलाधिकारी को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया गया था। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 19 फरवरी 2024 को डिफेंस अधिकारियों को उक्त मामले में भेजे गए पत्र को भी पेश करते हुए दावा किया गया है कि लगभग 13391 एकड़ जमीन सेना के रायफल रेंज के तौर पर संरक्षित है। जो कैंट क्षेत्र के कई गांवों में विस्तारित है। आरोप है कि उक्त जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं।

पीठ को सेना की ओर से बताया गया कि उसके फायरिंग रेंज की जमीनों पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। बताया गया कि राज्य सरकार ने

20 जनवरी 2021 को उक्त 14 गांवों की जमीनों के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की थी। जिसका

मकसद फायरिंग रेंज होने के कारण किसी दुर्घटना से नागरिकों को बचाना था।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोर्ट रूम में ही सील किया चायनीज लहसुन

विधि संवाददाता। लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को उपस्थित हुए फूड सेफ्टी व ड्रग प्रशासन विभाग के अधिकारी विजय सिंह ने कोर्ट रूम में ही कथित चायनीज लहसुन को सील किया। बीते गुजवार को पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आधा किलो प्रतिबंधित चायनीज लहसुन प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव का कहना है कि यह चायनीज लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह 2014 से ही यह भारत में प्रतिबंधित है। बावजूद इसके यह बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। पीठ के समक्ष हाजिर हुए

अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि चायनीज लहसुन की सूचना देने के लिए विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर 18001805533 जारी किया गया है। उनका यह भी कहना था कि तीन टीमें बनाकर राजधानी के तमाम मॉडियों में छापेमारी भी की गई है। लेकिन अब तक चायनीज लहसुन की बरामदगी नहीं हो सकी है। जस्टिस राजन राय एवम जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की पीठ ने इस पर मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर के लिए नियत कर दी है। साथ ही वर्ष 2014 के उक्त आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का भी आदेश दिया। पीठ ने यह भी पता करने को कहा है कि प्रतिबन्ध के बावजूद उक्त लहसुन की सप्लाई कैसे हो रही है।

अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग गठित

लखनऊ। राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक वैजनाथ रावत को मनोनीत किया गया है। वैजनाथ भुलभुलिया, मजरा व पोस्ट सेमरावां, भामा कोठी, विकास खण्ड सिधौर, बाराबंकी के रहने वाले हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर जीत सिंह खारवार निवासी ग्राम कुशमहा, पोस्ट गोविन्दपुर, सोनभद्र को मनोनीत किया गया है। जबकि सदस्यों में हरेन्द्र जाटव निवासी ग्राम पल्हेड़ा, पोस्ट मोदीपुरम, मेरठ, महिपाल वाल्मीकि निवासी ग्राम व पोस्ट हरीौड़ा, सहारनपुर, संजय सिंह निवासी सेक्टर 3, हाउस नं. 12 ग्रेटर ग्रीन पार्क, बरेली, दिनेश भारत निवासी ग्राम मन्दरा, पोस्ट नगला सबला, आगरा, शिव नारायण सोनकर निवासी ग्राम भरखा सुमेरपुर, पोस्ट सुमेरपुर, हमीरपुर, नीरज गौतम निवासी ग्राम व पोस्ट सेहुदर, औरैया, रमेश कुमार तूबानी निवासी बारा बखियारी मण्डौं, काली बाड़ी मार्ग, लखनऊ, नरेन्द्र सिंह खखूरी निवासी 188, मानसरोवर, गली नम्बर जीरो, निकट मवाना बस अड्डा, मेरठ, तीजारा ग्राम गुरेष्ठ, पोस्ट खरगपुर, आजमगढ़, विनय राम गुलौरी रतनपुरा, थाना हलधरपुर, मऊ, अनिता गौतम निवासी ग्राम मुडेवकालों, थाना इटियाथोक, गोण्डा, रमेश चन्द्र ग्राम व पोस्ट गोविन्दपुर, कानपुर, मिठाई लाल ग्राम सभा रामकिशुनपुर बसही, पोस्ट ऊज, भदोही, उमेश कठेरिया 575, बालजती, कठरा चौदखौं, पुराना शहर, बरेली, जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सेवड़ा, पोस्ट शेरगढ़, तहसील चायल, कौशाम्बी, अनिता कमल निवासी ग्राम व पोस्ट जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर को मनोनीत किया गया है।

भाजपा सरकार में अन्नदाता चौतरफा संकटों से घिरा हुआ: अखिलेश यादव

● किसानों को खाद-बीज और अन्य सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध करा पा रही सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसान उपेक्षा का शिकार है। भाजपा ने किसानों से आय दोगुनी करने से लेकर अन्य कई बड़े-बड़े वादे किये लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। यह सरकार किसानों को खाद-बीज और अन्य सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है। किसानों को आलू, गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरकों की आवश्यकता है लेकिन कन्नौज, मैनपुरी, सम्भल समेत अन्य जिलों के किसान डीएपी खाद और उर्वरकों के लिए अटक रहे हैं।



सहकारी समितियों पर उर्वरक नहीं है। सम्भल में डीएपी के लिए किसान दिनभर लम्बी-लम्बी लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। फिर भी खाद नहीं मिल रही है। किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्नदाता चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है। तराई जिलों में किसान बाढ़ से पीड़ित हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर

और सीतापुर में भंडिया और जंगली जानवरों से किसानों और आम लोगों में दहशत और परेशानी है। जंगली जानवरों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह से छट्टा जानवरों के कारण भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है लेकिन यह सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन है। भाजपा सरकार में पूरे सिस्टम पर भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता हावी है। किसानों को लेकर हमेशा इस सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण रहा है। भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी थीं और शोषणकारी है। किसानों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का किसान भाजपा के झूठ और लूट को समझ चुका है। अब किसान इस सरकार को बर्दास्त नहीं करेगा। आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनहानि से प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुमन्य राशि प्रदान करने के लिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेज बारिश के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए राहत कार्य पर प्रमुखा से नजर रखें और प्रभावित लोगों को भरपूर मदद प्रदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत राशि अखिलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें सहायता मिल सके। इस पहल के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आवश्यक सहायता मिले। विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तकता व मॉनीटरिंग समिति कार्य करती है, जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय स्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार ने पीड़ित दलित परिवारों के लिए आवंटित किए 1400 करोड़ से अधिक रुपए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। योगी सरकार ने हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को साढ़े सात वर्ष में 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर वित्तीय

● विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी/एसटी परिवारों को यूपी में 85,000 से लेकर 8.25 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता

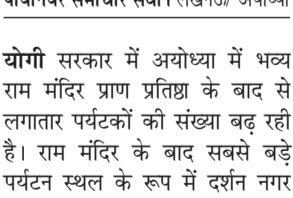
सहायता प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरत पर सरकार की तरफ से मदद मिले। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह सहायता 85,000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक होती है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर

आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें सहायता मिल सके। इस पहल के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आवश्यक सहायता मिले। विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तकता व मॉनीटरिंग समिति कार्य करती है, जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय स्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है।

पर्यटकों को लुभा रही है प्रभु श्री राम की नगरी सूर्यकुंड व गुप्तार घाट बने आकर्षण का केंद्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

योगी सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। राम मंदिर के बाद सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में दर्शन नगर स्थित सूर्यकुंड उभरा है। यह दर्शनार्थियों और पर्यटक के आगमन से और चमक उठा है। अकेले सितंबर माह में ही यहां 50 हजार के करीब पर्यटक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गुप्ताघाट का गुप्त हरि गाडेंन भी पर्यटकों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है। अगर अयोध्या में तीसरे नम्बर पर सबसे अधिक पर्यटक जाने वाले स्थल की बात करें तो वह गुप्त हरि गाडेंन के रूप में सामने आ रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने जब से अयोध्या के लिए खजाना खोला है। तब से रामनगरी विश्व के फलक पर



चमक रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या के विकास पर नजर टिकाए हुए हैं। अयोध्या में विकास कार्य चला रहें करौड़ की परिोजनाओं आये दिन सीएम समीक्षाएं भी करते हैं। इसी का नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही पर्यटन स्थल और मठ-मंदिरों का भी सौन्दर्यीकरण कराया गया है। इनमें सूर्यकुंड और अयोध्या कैंट स्थित गुप्त हरि गाडेंन छा गया है। लगभग रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद से अब तक तीन करोड़ श्रद्धालुओं ने

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हजरत दादा मियां की दरगाह पर पेश की चादर

● देश के विकास व सौहार्द के लिए मांगी दुआएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

महान सूफी संत हजरत दादा मियां साहब के 117 वें उर्स के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने माल एवेन्यू स्थित हजरत दादा मियां की दरगाह पर चादर पेश की तथा प्रदेश वासियों के अमन चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ की। इस अवसर पर लगाए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक सद्ब्व के साथ समाज में मानव कल्याण के साथ धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के



पैरोकार रहे सूफी संत, ऋषि मुनियों की परम्परा पर चलकर ही मानव सेवा की जा सकती है। आज हम सबने यहां दुआये मांगी हैं और

प्रार्थना की है कि महान सूफी संत हजरत दादा मियां साहब हमें शक्ति दे कि हम राष्ट्र व समाज के लिए अपनी प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता के नैतिक दायित्वों को पूरा कर सकें। राय ने कहा कि सूफी, संतों ने मानव कल्याण के लिये अपना जीवन समर्पित किया, उनके इसी समर्पण के भाव को कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. मसूद अहमद, प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी, डॉ. शहजाद आलाम, सिद्धार्थिया श्रीवास्तव, अखर आजमी, शाहनवाज खान, अखर मलिक, नितान्त सिंह, अनिस अख्तर मोदी, नीसम अहमद, शमशुल हसन उमरा, सलीम सूरी प्रमुख रूप से साथ मौजूद रहे।

विजिटर्स को हो रहे 'रामायण दर्शन', एआई से सृजित किए गए अद्भूत प्रसंग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा

सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान हर कहीं हैं। वो सर्वत्र हैं, कण-कण में हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश में कोई आयोजन हो और भगवान राम वहां न हों। ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण (यूपीआईटीएस 2024) में भी विश्व की सनातन संस्कृति के प्राण प्रभु श्रीराम और उनकी नगरी अयोध्या को सृजित किया गया है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के माध्यम से। एआई रामायण दर्शन के नाम से एक पवेलियन को यहां स्थापित किया गया है, जिसमें सभी इमेजेस को एआई की मदद से जेनरेट किया गया है। इस पवेलियन में अयोध्या को उसके पुरातन वैभव की कल्पना के अनुरूप वास्तविक छवि में प्रस्तुत किया गया है तो भगवान राम के जीवनकाल से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को भी भव्य तरीके से दर्शाया गया है। इस मनोरम पवेलियन में इन सभी छवियों के बीच बैकग्राउंड में बजता राम सिया राम का म्यूजिक इसकी आभा को और निखार रहा है तो वहीं यह लोगों की आस्था और आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से 'रामायण दर्शन' नाम के स्टॉल को स्थापित किया गया है। यह एआई जेनरेटेड रामायण है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के सभी प्रमुख प्रसंगों की झलक विजिटर्स को देखने को मिल रही है। जिन प्रसंगों को यहां पर दिखाया गया है उसमें भगवान श्रीराम द्वारा भाइयों के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, लंका दहन और रावण कथ प्रमुख रूप से शामिल हैं। एआई के माध्यम से निर्मित छवियों में रामायण के सभी पात्रों में सादगी और वैभव, वास्तविकता और विरासत तथा परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आवश्यक सहायता मिले। विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तकता व मॉनीटरिंग समिति कार्य करती है, जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय स्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने राजोआना की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को उसकी ओर से दायर दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। राजोआना ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को उसकी ओर से दायर दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। याचिका में कहा गया है कि इसलिए उसकी रिहाई के लिए निर्देश जारी किया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष तीन मई को राजोआना को सुनाई गई मौत की

सजा को उप्रकेद में बदलने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी नई याचिका में राजोआना ने कहा है कि उसने कुल मिलाकर लगभग 28 साल और आठ महीने की सजा काटी है, जिसमें से 17 साल उसने मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी के रूप में काटी है। राजोआना पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और उसे 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था। इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने राजोआना को जुलाई, 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। उसकी याचिका पर 25 सितंबर को न्यायमंत्री बी. आर. गवंई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

पीठ में न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया जाता है और इस पर चार नवंबर को जवाब

दाखिल किया जाए। राजोआना ने अपनी याचिका में कहा है कि मार्च 2012 में शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसकी ओर से क्षमादान का अनुरोध करते हुए संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक दया याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया है कि एक साल से अधिक समय बीत चुका है, जब उच्चतम न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारों को उसकी ओर से दायर दया याचिका पर विचार करने और उस पर आगे निर्णय लेने का निर्देश दिया था। याचिका में एक अलग मामले में उच्चतम न्यायालय के पिछले साल अप्रैल के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने सभी ग्यों और उपयुक्त प्राधिकारियों को लंबित दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के फैसला करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया, उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, याचिकाकर्ता की दया याचिका को लंबित रखा गया है।

लोकपाल ने पत्रकारों से मान्यता के लिए आवेदन करने, ड्रेस कोड का पालन करने को कहा

नई दिल्ली। लोकपाल ने इसके कामकाज को कवर करने के वास्ते पत्रकारों से मान्यता के लिए आवेदन मांगे हैं और पात्रता मानदंडों की एक सूची जारी की है जिसमें इसके परिसर में आने के दौरान मॉडियाकर्मियों के लिए एक ड्रेस कोड शामिल है। पत्रकारों के पास अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार भारतीय विभिन्न परिपद से मान्यता प्राप्त कानूनी डिग्री होनी चाहिए। यदि पत्रकार या संवाददाता के पास किसी मान्यता प्राप्त विवि वे स्नातक की डिग्री है तो लोकपाल अध्यक्ष द्वारा उचित मामलों में इस शर्त को माफ या शिथिल किया जा सकता है। इच्छुक पत्रकारों के पास किसी भी संवैधानिक अदालत की घटनाओं और कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का कम से कम पांच साल का अनुभव होे। इच्छुक पत्रकारों के पास दैनिक समाचारपत्र या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठान में रिपोर्टिंग का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। साढ़े तीन साल का अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि परिपत्र जारी होने से 30 दिन है। मान्यता के बाद श्रमजीवी पत्रकार/संवाददाता द्वारा पादान की जाने वाली शर्तों का उल्लेख करते हुए मानदंडों में कहा गया है कि एक मान्यता प्राप्त संवाददाता, अस्थायि/नियमित, कार्यालय के माहौल के अनुरूप औपचारिक पोशाक में लोकपाल परिसर का दौरा करेगा।

डीयू, कॉलेजो ने लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशो वी अनदेखी की: डूसू चुनाव पर दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और इसके कॉलेजों के अधिकारी लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के सही मायने को समझने में विफल रहे हैं, जिनमें छात्र संघ चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मुद्रित पोस्टर्सों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। अदालत ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अधिकारियों ने लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों को अवहेलना की है। नामित मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार रव गडेला की पीठ ने 26 सितंबर के अपने आदेश में ए टिप्पणियां कीं। इस शुकवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

अदालत ने अपने इस आदेश के जरिए पोस्टर, होर्डिंग हटाए जाने और भित्तिचित्रों को मिटाए जाने तथा

सार्वजनिक संपत्ति को पूर्व रूप में लाने तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों की मतगणना रोक दी है। डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को यहां विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों (नॉर्थ और साउथ कैम्पस) में कड़ी सुरक्षा के बीच दक्षिणी परिसरों (नॉर्थ और साउथ कैम्पस) में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मतों की गिनती शनिवार को होनी थी।

पीठ ने कहा, इस अदालत को ऐसा भी लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और डीयू के कॉलेजों के वरिष्ठ प्रबंधन इस अदालत द्वारा स्वीकार किए गए लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के वास्तविक महत्व और आवश्यकता को समझने में लापरवाही बरत रहे हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो और तस्वीरों को देखने के बाद, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका मानना है कि डूसू और डीयू के

धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी हटाई, आरोपी को जमानत दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को फैसेले से हटा दिया कि यदि धार्मिक आरोपजनों, जहां धर्मांतरण होता है, को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कैलाश नामक व्यक्ति की जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए राहत दी कि वह 21 मई, 2023 से हिरासत में है। पीठ ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों का

वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं था और इसलिए, मामले के निस्तारण के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी। इन टिप्पणियों को उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत में किसी अन्य मामले या कार्यवाही में उद्धृत नहीं किया जाएगा। इससे पहले दो जुलाई को, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आरोपों पर गौर किया था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों को धर्मांतरण के लिए दिल्ली में एक धार्मिक समागम में ले जा रहा था और कहा था, अगर इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई, तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी...। उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का धर्मांतरण संविधान के खिलाफ है, जो केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार की अनुमति देता है।

आरजी कर के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ आरोप गंभीर, फांसी की सजा हो सकती है: अदालत

कोलकाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामलों में सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने कोलकाता स्थित आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनके साबित होने पर फांसी की सजा तक हो सकती है। सीबीआई ने नौ अगस्त को सरकारी अस्पताल में एक चिकित्सक से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आरोप पर घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था।अदालत ने 25 सितंबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा कि केस डायरी से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा

जांच की प्रक्रिया जोरों पर है। घोष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस डे ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यदि ए साबित हो जाते हैं तो इसमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, जो दुर्लभतम मामलों में दी जाती है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की राय है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने आदेश में कहा कि एक व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और अन्य आरोपियों को घटना स्थल पर मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने अभिजीत मंडल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इसने 30 सितंबर तक दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

पेज 1 का शेष सुप्रीम कोर्ट ने...

अदालत में उपस्थित हुए सीएन्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पीठ को बताया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा के जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की है, जहां पर पारली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं।शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को सुनाए से कहा था कि वह सुनवाई की अगली तारीख (27 सितंबर) को इस मुद्दे पर उद्घाटण गए कदमों की जानकारी दे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पहले कहा था कि सदस्यों के दौरान दिल्ली-पनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि एक कारण पारली जलाना भी है। पिछली सुनवाई के दौरान 27 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कर्मचारियों की कमी के कारण दिल्ली और पनसीआर के ज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अप्रभावी करार दिया था और राष्ट्रीय राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय से यह बताने के लिए कहा था कि वह प्रदूषण एवं पारली जलाए जाने की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहा है।शीर्ष अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि रिकॉर्डों के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रतिनिधित्व की कमी है, ऐसे में सीएन्यूएम द्वारा गठित सुरक्षा और परिवर्तन पर उप-समिति कैसे कार्य करेगी।न्यायालय ने पनसीआर के पांच राज्यों को संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को 30 अप्रैल 2025 से पहले भरने का निर्देश दिया है।

बिहार में...

बारिश होने की उम्मीद है। बुलेटिन में कहा गया है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी

चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों में अगले 24 घंटों में 'हल्के से मध्यम स्तर की बाढ़' आने का खतरा है। प्रभावित जिलों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।हिमाला मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश के लिए 'चेते' अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में एक-एक सड़क बंद है। अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 27 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर बृहस्पतिवार शाम तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 185 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को 1,332 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

भाजपा का...

के 'एकाधिकार मॉडल' ने देश में नौकरियां छीन ली हैं।' बुधवार को जम्मू में अखिल भारतीय व्यवसायिक कांग्रेस (एआईपीसी) द्वारा आयोजित 'डोगरी धाम विदे आरजी' कार्यक्रम का वीडियो साझा करते हुए राहुल ने कहा कि 'येते' अलर्ट जारी के एक युवा स्टार्ट-अप मालिक की आंखों में निराशा भारत के अधिकांश उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के संघर्ष को



नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को उन सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का लंबित वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का शुक्रवार को निर्देश दिया जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था। न्यायालय ने पूछा कि आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग नहीं हो सकती।

एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 31 मार्च, 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर

मार्च, 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डी. वार्ड, चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपीलों पर गौर किया। पीठ ने तब अप्रसन्नता जाहिर की जब आयुष चिकित्सकों के वकील ने कहा कि हालांकि उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया है, लेकिन उनके वेतन के भुगतान में पांच महीने की देरी हुई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, वे सभी चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों...आपने वेतन जारी क्यों नहीं किया? पीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने को कहा।

पीठ ने वकील से राज्य में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित मुद्दे से उत्पन्न मामलों का एक चर्चा तैयार करने को कहा।

हवारा को पंजाब की जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। हवारा 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस घटना में 16 अन्य लोग भी मारे गए थे। उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि जेल में हवारा का आचरण ठीक रहा है, सिवाय एक कथित घटना को छोड़कर

विश्वनाथन की पीठ ने हवारा की याचिका पर केंद्र, दिल्ली और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हवारा 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में सिंह की हत्या से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस घटना में 16 अन्य लोग भी मारे गए थे।

उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि जेल में हवारा का आचरण ठीक रहा है, सिवाय एक कथित घटना को छोड़कर

जिसमें वह 22 जनवरी 2004 को जेल में सुनां खरादकर फगर हो गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पीठ ने हवारा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गॉजाव्लिस से पूछा, आप (हवारा) सुंग्र खोदने में कैसे सफल रहे? गॉजाव्लिस ने कहा, आज, मुख्य घटना को हुए लगभग 30 साल और जेल से भागने की घटना को हुए 20 साल हो गए हैं।

पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

^[1] नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को फैसेले से हटा दिया कि यदि धार्मिक आरोपजनों, जहां धर्मांतरण होता है, को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी

^[2] नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को फैसेले से हटा दिया कि यदि धार्मिक आरोपजनों, जहां धर्मांतरण होता है, को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी

^[3] नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश उपलब्ध कराने के लिए एक नया वेब पेज शुरू किया है

^[4] नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश उपलब्ध कराने के लिए एक नया वेब पेज शुरू किया है

^[5] नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश उपलब्ध कराने के लिए एक नया वेब पेज शुरू किया है

कॉलेज के चुनावों में धन एवं बाहुबल का व्यापक उपयोग हुआ है जो लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा, इस अदालत का मानना है कि चुनाव, जिसे लोकतंत्र का त्योहार माना जाता है, को धनशोधन और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के त्योहार में बदल दिया गया है। कुछ मायनों में, यह शिक्षा प्रणाली की विफलता की दर्शाता है। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को विरूपण सामग्री हटाने में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), सरकारी विभागों और दिल्ली मेट्रो सहित नगर प्राधिकारों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि विवि को इसके बाद, लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों से राशि वसूलने का अधिकार होगा।

एमएसपी का पूरा मतलब भी जानते हैं राहुल : शाह

● हरियाणा के किसानों के लिए केंद्रीय योजना का लाभ 4000 रुपए बढ़ाने का वादा किया

भाषा। रेवाड़ी-कुश्केत्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी पांच अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में आती है तो हरियाणा के किसानों के लिए केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वह एमएसपी का पूरा मतलब भी जानते हैं ? साथ ही



उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीद रही है। रेवाड़ी, अंबाला और कुश्केत्र जिलों में रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने वादा किया कि आरूपमान भारत योजना के तहत मुक्त इलाज की सीमा पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में लौटेगी।उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीद रही हैं। रेवाड़ी, अंबाला और कुश्केत्र जिलों में रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने वादा किया कि आरूपमान भारत योजना के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने

झारखंड में भारी भ्रष्टाचार, बिना पैसे के कुछ नहीं होता: शिवराज

भाषा। रांची

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को झारखंड को झामुमो नीत गठबंधन सरकार पर विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य को भेजे गए केंद्रीय धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि मनरेगा के लिए मिले धन के उपयोग की जांच शुरू की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार पर सीधा हमला करते हुए उसे पेपर लीक सरकार करार दिया और उस पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। लातेहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की



परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, झारखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के यहां कुछ नहीं होता। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए आए केंद्रीय धन का जमकर दुरुपयोग किया। हम मनरेगा में अनियमितताओं की गहन जांच शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग झामुमो नीत गठबंधन को उसके कुशासन के

लिए कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से इस वर्ष के अंत में होने वाले 81 सदस्यैय झारखंड विधानसभा के चुनावों की माँग की। हेमंत सोरेन सरकार के अत्याचार, आतंक और कुशासन के कारण लोग लगातार भय में जी रहे हैं।उन्होंने कहा, पूरा देश देख रहा है कि कैसे झामुमो झारखंड के युवाओं को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर उनकी सोंसैं छीन रही है। सत्ता के मद में अंधी हो चुकी सरकार को युवाओं का दर्द, उनकी बेवसी नहीं दिख रही।

कांग्रेस के चुनावी वादों से हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा: गहलोत

भाषा। चंडीगढ़

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा के लोगों के लिए दी जा रही गारंटी से न तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। गहलौत ने पत्रकारों से कहा कि ए गारंटी व्यापक विचार-विमर्श और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श के बाद दी गई हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनता से चर्चा करने, उनके विचारों को समझने और आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि एक बार ए गारंटी लागू हो जाएं तो हरियाणा एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा। गहलौत ने इस दावे को खारिज कर दिया कि कांग्रेस ने केवल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हरियाणा के लोगों से बड़े-बड़े वादे किए हैं। राजस्थान में किए कार्यों का उदाहरण देते हुए गहलौत ने कहा कि हरियाणा के लोगों को दी गई कई गारंटी राजस्थान में पहले ही लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 लाख रुपए तक की मुक्त स्वास्थ्य सेवा योजना सफल तरीके से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू किया गया है।

लालू प्रसाद और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ प्राप्त किया: ईडी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां को एक अदालत से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (एजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गंगने के समक्ष इस मामले में दायर अपने पूरक आरोपपत्र में ए दलीलें दीं। अदालत ने 18 सितंबर के अपने आदेश में प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी तलब किया था, जिन्हें जांच एजेंसी ने आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है।न्यायाधीश ने कहा, अदालत को प्रथम दृष्टया और समन के चरण में आवश्यक जांच के मानक के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्यकारी आधार मिलता है कि तेज प्रताप यादव भी अधिग्रहण और अपराध को आय को छिपाने में शामिल थे और इस प्रकार वर्तमान पूरक शिकायत पर तलब किए जाने के लिए उत्तरदाई हैं। उन्होंने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी तलब किया।न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रसाद, उनके दोनों बेटों और अन्य को सात अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।न्यायाधीश ने पहले इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों – मीसा भारती और हेमा यादव को तलब किया था।

जगन को तिरुमला जाने से नहीं रोका गया : नायडू

भाषा। अमरवती

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सुप्रिमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे अधिकारियों ने उन्हें तिरुमला मंदिर जाने से रोका है। नायडू ने पूछा कि क्या उन्हें (जगन को) मंदिर नहीं जाने के लिए कोई नोटिस दिया गया था।नायडू ने तिरुपति भगवान कंठेश्वर मंदिर में अनुष्ठान करने की योजना को स्थगित करने के जगन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर धार्मिक स्थान की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं और जो कोई



भी पूजा स्थल पर जाना चाहता है उसे वहां अपनाए जाने वाले बंधनों का सम्मान करना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि जगन का यह कहना कि वह अपनी आस्था को साबित करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए बगैर भी तिरुमला मंदिर जा चुके हैं, उन्हें उस गलती को दोहराने का अधिकार नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा, युझे नहीं पता कि उनके (जगन) तिरुमला न जाने

जगन मोहन रेड्डी ने तेदेपा, भाजपा पर निशाना साधा, अपना तिरुमाला दौरा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया

अमरावती (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश केविपक्षी दल युवजन श्रमिकरायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने तिरुपति भगवान कंठेश्वर मंदिर का अपने निवासि दौरे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।इस मंदिर में प्रवेश से पहले अपनी आस्था स्पष्ट करने वी आंध्र प्रदेश केसत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनताधिक गठबंधन (एनएम) केउपक दलों वी भाग केबीबी उन्होंने यह घोषणा की।वर्षा का कैं बने (जगन के) इस दौर वी घोषणा उनकी दाईं तरफ आहूत रचनाएकी मंदिर प्रार्थना अनुष्ठान के तहत दी गई थी ।

के पीछे का क्या कारण था, लेकिन वे ऐसा दावा कर रहे थे जैसे उन्हें रोका गया हो और नोटिस जारी किया गया हो। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ। क्या आपको कोई नोटिस दिया गया है? क्या किसी ने आपसे वहां न जाने के लिए कहा? ऐसी खबरें आ रही थीं

कि वाईएसआरसीपी, जगन के मंदिर दौरों को लेकर लोगों को जुटाने के लिए सुचना फैला रही थीं ताकि पुलिस को प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा।नायडू ने कहा, परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए।

रेरिख की दुनिया काव्य में, पुस्तक का विमोचन

नई दिल्ली। आज दिल्ली केरशियन हाउस मेंएक विशेष समारोह में प्रेरिख की दुनिया काव्य में शीर्षक से एक अनूठी पुस्तक का विशिष्ट अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। यह पुस्तक महान रूसी कलाकार विचारक,वैज्ञानिक, लेखक, कवि और दार्शनिक . निकोलाय रेरिख के जन्म की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। रेरिख की सभी रचनाएँ जैसे चित्रकला ए कविताएँ परी कथाएँ लेख, निबंध इत्यादि एक ही मातासगर की तरंगों केसमाान हैं।ए जो एक दसर् ूके पूरक हैं। पुस्तक की लेखिका प्रोफे सर मीता नारायणए रूसी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वाना हैं। जिनकी लिखी अनेक पुस्तकें दनु या भर के अनेक विश्वविद्यालयों मेंपढ़ाई जाती हैं।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी अध्ययन केंद्र की पूर्वप्रोफे सर व अध्यक्ष नरेरिख के व्यक्तित्व के एक अनछूए पक्षए उनके काव्य को अंग्रेजी और हिन्दी मेंप्रकाशित करकेसाहित्य जगत की अनुपम सेवा की है। रेरिख की दनु याए काव्य में रेरिख के प्रारंभिक जीवनए उनकी रचनात्मक कलाए भारत के साथ उनकोध्यात्मिक संबंधों उनकी दार्शनिक अवधारणाओं और कला और संस्कृती के प्रति उनके अटूट प्रेम सेअलगत करती है। इसमेंहिमालय पर्वतमाला व भारत की आध्यात्मिक पहचान पर रेरिख द्वारा उके रेग्येअनेक मनभावन चित्र भी दियेगयेह, जो हमेंउनकी रचनात्मक प्रतिभा को समझनेमेंमदद करतेहैं। एक कवि के रूप में

निकोलाय रेरिख विश्व के इतिहास मेंएक प्रसिद्ध शख्सियत हैंए इसलिए पुस्तक का मुख्य भाग रूसी भाषा सेअंग्रेजी और हिंदी में उनकी कविताओं के अनुवाद को समर्पित है। रेरिख की कविताओं के अनुवाद पहलेभी हुए हैंए लेकिन इस बार किए गए अनुवाद, अद्भुतदृष्टि चित्रों केसाथ उनकी कविताओं के मर्मऔर रस को और अधिक सहज और सघन बनातेहैं। प्रोफे सर मीता नारायण भारत और विदेशों मेंरूसी भाषाशास्त्र के क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करनेमेंउनके योगदान के लिए एबुधियान मेडल ,2019दृ संसमानित हैंऔर उनकी यह पुस्तक रूस और भारत के बीच संबंधोंको मजबूत करनेमेंउनके योगदान को और आगेबढ़ाएगी।

लाइसेंस मुक्त वॉकी-टॉकी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा

मुंबई। भारत में बिना लाइसेंस वाली वॉकी-टॉकी का उपयोग बढ़ गया है और यह भारत सरकार के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। मुख्य रूप से चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित, ये उपकरण भारत और म्यांमार के दूरदराज इलाकों में ही नहीं, बल्कि महानगरीयों में भी सक्रिय विद्रोही समूहों, माओवादियों और सैन्य, विरोधी बलों द्वारा पसंद किए जाते हैं। उनके बढ़ते उपयोग ने राष्ट्रीयपी असुरक्षा को उजागर कर दिया है और स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सुरक्षा दलों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इस खतरें पर सावधानीपूर्वक विचार करने से पता चलता है कि इन बिना लाइसेंस वाले वॉकी टॉकी उपकरणों का उपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगे समूहों के बीच अधिक प्रचलित है। क्योंकि ये उपकरण बहुत सस्ते हैं।ए आसानी से उपलब्ध हैं और इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इनकी कीमतें 1,800 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक हैं। यह वॉकी-टॉकी छत्तीसगढ़ के जंगलों या उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के कटोरे वातावरण में भी सक्षम रहते हैं। इन उपकरणों के साथ एक बड़ी चिंता यह है कि इनके तकनीक के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सरकार द्वारा निर्धारित 0.5 वाट की सीमा से आगे जाकर इनकी क्षमता 5 वाट या उससे भी ज्यादा तक बढ़ाई जा सकती है। इससे उनकी सीमा बढ़ जाती है और लंबी दूरी तक संचार संभव हो जाता है। यह अवैध हेरफेर विद्रोही समूहों को रणनीतिक लाभ देता है।ए जिससे उन्हें हमलों का समन्वय करने और सुरक्षा बलों द्वारा पता लगाने से बचने की अनुमति मिलती है। इन उपकरणों का डिज़ाइन बहुत सरल है। इसलिए कम तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति भी इन उपकरणों को संचाल और उपयोग कर सकते हैं। इन वॉकी-टॉकी का बढ़ता उपयोग केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह भारत सरकार के लिए एक वित्तीय और परिचालन समस्या भी है। अवैध उपकरणों का बढ़ता प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए नियामक ढांचे को भी खत्म कर देता है।

मक्सी में हिंसा मग्न भाजपा के सदस्यता अभियान के कारण हुई: दिग्विजय

भाषा। शाजापुर (मध्यप्रदेश)

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी में इस सप्ताह हिंसा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यता अभियान के कारण हुई। भाजपा ने सिंह के आरोपों को निराधार और भ्रामक करार दिया। मक्सी में बुधवार रात करीब 9.30 बजे दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। दोनों समूहों के सदस्यों ने पत्थर फेंके और आगजानसत्ता का इस्तेमाल किया। जिला अधिकारियों के अनुसार, हिंसा सोमवार को दो समूहों के बीच हुए उत्क्राव का नतीजा थी। मक्सी जिला मुख्यालय के करीब 25 किलोमीटर दूर है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, मक्सी में हुई घटना पूरी तरह से भाजपा के सदस्यता



अभियान के दौरान खले जा रहे दबाव का नतीजा थी। लोगों से खुलेआम कहा जा रहा है कि वे भाजपा के सदस्य बनें या सीने में गोली खा लें। सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे। वे अमजद खान के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। खान की मौत झड़प में गोली लगने से हुई थी, खान के भाई अनवर ने सिंह को घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सिंह ने मक्सी के पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक के तबादले के साथ ही जेल

आर.जी. क्व मामला : सीबीआई को अपराध स्थल की सटीकपहचान के लिए 3डी मैपिंग रिपोर्ट का इंतजार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित सरकारी आर.जी. कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या मामले की जांच कर रही एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अपराध स्थल की सटीक पहचान करने के लिए आपातकालीन वार्ड भवन की 3डी लेजर मानचित्रण रिपोर्ट का इंतजार है। एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर तय किया जा सकेगा कि महिला चिकित्सक को कहाँ यातना दी गई और उसकी हत्या की गई। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि केंद्रीय एजेंसी को उम्मीद है कि 3डी मैपिंग रिपोर्ट आने पर साक्ष्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ करने का खुलासा होने की उम्मीद है। एजेंसी के एक अन्य सूत्र ने पुष्टि की कि 30 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय में पेश की जाने वाली जांच की वस्तु स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई अपने निष्कर्ष भी पेश करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या की जांच कर रही है।

बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, अचानक बाढ़ की चेतावनी

पटना। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और अगले 24 घंटे में राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिमी घाटवार, पूर्वी घाटवार, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मुधुनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में अगले 24 घंटे में अचानकबाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मद्देनजर राज्य के आधा प्रदेयन विभाग (डीएमडी) ने इन 13 जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और स्थिति को संभलाने के लिए सभी निवाटक उपाय करने को रखा है। डीएमडी ने शुक्रवार को इस संबंध में इन 13 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में झारखंड के आईएस अधिकारी समेत कई के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के भद्राचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) एवं आर्थिक अपराध शाखा (ईओइब्ल्यू) ने झारखंड के एक वरिष्ठ आईएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के एक सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी समेत सात लोगों के खिलाफ झारखंड में शराब नीति में बदलाव क झारखंड संस्कार के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि झारखंड के रांची निवासी विवेक कुमार की शिकायत के आधा पर सात सितंबर को आईपीडी की धारा 420 (मोटाखाड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पूर्व आईएस अधिकारी अनिल टुंजा, च्यावर्डी अनवर बेबर, छत्तीसगढ़ राज्य विधान निगम लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ निदेशक अरुणापति त्रिपाठी, आईएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व आवक्ती अत्युक्त निरन्तर दास तथा अरविंद सिंह (सभी छत्तीसगढ़ के), झारखंड के पूर्व आवक्ती सचिव विनय कुमार चौधे (1999 बैच के झारखंड कैडर के आईएस) और जोराड़ के च्यावर्सी विधु गुप्ता शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा मेसर्स सुमित फेरिलिटीज के निदेशक, मैनाघाट एजिसिया, शराब आपूर्तिकर्ता एजिसिया और राज्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। टुंजा, बेबर, त्रिपाठी, दास और सिंह छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ शराब घोटाले में भी आरोपी है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ की एसीबी,ईओइब्ल्यू कर रही है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ शराब घोटाला राज्य की पिछली चर्चोस संस्कार के दौरान सामने आया था।

प्रभावशाली धुनों और चंचल बोलों से रुबरु होंगे दर्शक

नई दिल्ली। अमरती प्रतिभाएं और देसी हिंग होंप करण की गतिशील जोड़ी और ननकू अपने जीवनमन सिंगल के साथ आएको स्मृति लेने में एक जनेदार युतिले साक्षर पर ले जाने के लिए तैयार है। अपनी प्रभावशाली धुनों और चंचल बोलों के लिए जाना जाने वाला यह जगन एकएम सही निश्र्वा है चंचल आकर्षण और प्रतिरोध गुरू एक एडको के अपने शिधक पर रुध के रोमांच को ताज़गी से कैद करता है। आधुनिक मोड, आकर्षक बीट्स और नगणिकी गीतों में लिपटी एक पुरुनी यादें अलसता में जनेदार शिखराड सब कुछ है। और पूरी तरह से सबिधत कलम पर करण और ननकू के साथ और संगीत करण ननकू और द्वारा तैयार किया गया है । आदिल जवल डिपार्ले मेगमन यह टुकें उन वलासिधे स्कूल रुध क्षणों को जीवित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आदिल का गुरुची प्रोडक्शन बेहतरीन फिनिशिंग टग जोड़ता है, जिससे यह गाना हृद गंभीर को कुरुष सुनना चाहिए जिसे सीधे धुन पदर है जो आपको साथ पिपक जाए। यह टुकें आधुनिकता के साथ रेप तत्वों को सहजता से जोड़ता है बीट्स एक गुरुची मिश्रण बनाने है जो प्राणिक और अगणी दोनों लगाने है। वृहे आप याद कर रहे हैं, आपके अपने स्कूल के दिनों के बारे में या बस एक आकर्षक अरख महसूस कराने वाली धुन के गूड में बलासकत तैयार है।

नैलासनेरी सिगारेट जब्त किए

नई दिल्ली। ग्राहक घेतना ट्टर से मिली सूचना और सुधिया जानकारी के आधार पर, पुलिस अधिकारियों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर दिल्ली कैट के दो बजारों में गैरकानूनी सिगारेट्स की छानबीन की। गोपीनाथ मार्केट में गुलाब टी स्टॉल जॉली पान, रगेरा पान, मोती पान और विशाल सहित कई दुकानों पर अवैध सिगारेट का कारोबार चल रहा था, इन दुकानों से 6१200 टी सिगारेट प्रतिबंधित सिगारेट जब्त किए गए, गिनका नूत्य नमामग 65,000 विधेपे साइडगी से पुलिस स्टेशन में जॉली पान, रगेरा पान, मोती पान, गुलाब टीड और बिशाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित सामग्री बेचने वाले अन्य लोगों और दुकानों को चेतावनी दे दी गई है। एकडे नए प्रतिबंधित सिगारेट्स में उन्डरहित, एस्से लाइट, एस्से स्ट्रोक गोटा, एस्से ट्रेजे सैल्वे,कैड, गुजान गरम और क्लेस शामिल है। परेशी में अवैध सिगारेट का व्यापार भारत में भी फैला हुआ है। गैरकानूनी और प्रतिबंधित उत्पादों की वरचसी के मार्ग पूरी दुनिया में है इसलिए यह किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, जिसे हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्धान करना है। इस बढ़ते अवैध व्यापार को रोकने के लिए कठोर नियमों और उनके प्रवर्तन के साथ गैरकानूनी व्यापार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। इस छोपमारी के बारे में जागरूक घेतना ट्टर के मुख्य ट्टरी सुदेश कौशिक ने बताया कि इन मामलों में हमारे द्वारा दी गई जानकारी की छानबीन करने और कार्रवाई करने के लिए हम कानून प्रवर्तन संस्था की सहजना करते है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का पालन करने वाला एकमात्र एल्युमीनियम उत्पादक बना वेदाता

नई दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग श्रीीआईआईटी ने एक विशेष आदेश जारी किया है जो कि आज से ही लागू है। इसके तहतार भारत में बेचे जाने वाले सभी एल्युमीनियम वाटए रॉड्स और टोल्स प्रोडक्टर जैसे. शीट्स प्लेट्स और स्ट्रिप्स को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रामाणित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में वेदाता एल्युमीनियम ने घोषणा की है कि वह इन प्रोडक्ट्स के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली और एकमात्र कंपनी है। यह प्रामाणीकरण छत्तीसगढ़ में कंपनी के बाल्को प्लांट और ओडिशा स्थित कंपनी की झारसुगुड झकाई में निर्मित किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए मिला है। भारतीय गुणवत्ता और उद्योग मंत्रालय तथा खन मंत्रालय ने 31 अगस्त 2023 को विधेपे साइडगी के तहत एल्युमीनियम और इसकी मिश्र धातुओं के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण नियम पेश किए। अनिवार्य रूप से बीआईएस प्रामाणीकरण के लिए सरकार द्वारा 26 सितंबर 2024 तक की समय सीमा दी गई थी लेकिन वेदाता एल्युमीनियम ने इसे पहले ही अपने प्रोडक्ट्स का प्रामाणीकरण करवा लिया। यह न सिर्फ़ उच्च गुणवत्ता मानकों के प्रति वेदाता की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बल्कि एल्युमीनियम इस्टडी में इसके नेतृत्व को भी मजबूत करता है। इस उपलब्धि पर दिवाणी करते हुए वेदाता एल्युमीनियम के चीफ ऑफ़िसर आरिफ़त सुनील गुप्ता ने कल कि प्रमाणन के लिए सरकार का आदेश एक सकारात्मक कदम है। जो सुनिश्चित करता है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमीनियम का ही उत्पादन और उपभोग है।

एमेजॉन इंडिया ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मुंबई। एमेजॉन इंडिया ने आज घोषणा करी कि उसने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके तहत एमेजॉन और उसके स्टॉफिंग एजिसियों में उपलब्ध नौकरों के अवसरों को पोस्ट करने के लिए मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस प्लानसीएसड पोटल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भारत में नौकरों की खाने वाले को नौकरों के अवसर देखने में मदद मिलेगी और एमेजॉन इंडिया और इसकी स्टॉफिंग एजिसियों को नौकरियों के अवसर को पोस्ट करने की और एनसीएस पोटल से सही उम्मीदवारों को चुनने में भी मदद मिलेगी। एनसीएस पोटल पर पंजीकृत नौकरों की खाने वाले एमेजॉन पर उपलब्ध बेहतर अवसरों को आसानी से खोज कर आवेदन कर सकेगे। एमेजॉन श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्लानसीएस पोटल के साथ सहयोग करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी है। इस साझेदारी का नकसद इच्छुक व्यक्तियों को उनके कौशल और योग्यता के हिसाब से करियर संभावनाओं से जोड़ना है। दीर्घ कालीन वार्डें प्रेसिडेंट एच.इसरायलील एएसपीरियंस और टेक्नोलॉगीए एमेजॉन स्टोर्सए मास्टार जापान और उमरते बजारों ने कल की रूम श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साझेदारी कर के बेहद उत्साहित है।ताकि हम अपने उम्मीदवारों की तलाश को एनसीएस पोटल से बेहद नेटवर्क के साथ जोड़ सकें। यह महत्वपूर्ण है कि हम पाे की सही जानकारी देें नौकरों बिलाने को और भी बेहतर करें।ए और नौकरों ढूँढने का एक आसान तरीका देें खासकर वरिष्ठ समुदायों के लिए।

रेडविलफ लैब्स देगा विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा

गोरखपुर। रेडविलफ लैब्स, जो पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है, ने लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में तीन अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब्स स्थापित करके उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। 20 से अधिक लैब्स और 500 कर्मियों सहित संरचना के साथ, यह विस्तार रेडविलफ लैब्स के मिशन भारत को सही डायग्नोस्टिक सेवा का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विस्तार न केवल महानगरों में, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी सुगुन, सटीक, और मरीसेंसमें सेवाएं उपलब्ध कराने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोरखपुर में, पोथालीजिस्ट डॉ. देवानु बरोहर द्रुने सांखल की देखरेख करेगे, जो गिनद, सखनवाण, ड्रग्स, पीएरइच और बसवाण जैसे क्षेत्रों में ट्यापक सेवा सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ में, जोनल नेबोटरी हेड डॉ. ज़िनेद महदुद सिंह के नेतृत्व में, लैब वहां के निवासियों के लिए आदर्श रूप से स्थित है, जो डायग्नोस्टिक्स के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है।

हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेंगे : नेतन्याहू

● यूएन में कहा इजराइल अपने लक्ष्य हासिल होने तक नहीं रुकेगा

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को विश्व के नेताओं से कहा कि लेबनान से लगी सीमा पर अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक उनका देश हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेगा। उनके इस बयान से, क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाले संघर्ष विराम की उम्मीदें घट गई हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उनको सरकार उस इलाके (लेबनान) से रोजाना रॉकेट दागे जाने को अब बर्दाश्त नहीं



करेगी। उन्होंने कहा, इजराइल को इस खतरे को खत्म करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घर भेजने का पूरा अधिकार है। और हम ठीक वहीं कर रहे हैं... हम हिजबुल्ला पर हमले करना जारी रखेंगे, जब तक कि हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने कहा, जरा सोचिए, यदि आतंकवादी एल पासो और सैन डिग्यागो को भूहाहा शहरों में बदल दे... अमेरिकी सरकार कब तक उसे बर्दाश्त करेगी? उन्होंने कहा कि फिर

भी इजराइल लगभग एक साल से इस असहनीय स्थिति को बर्दाश्त कर रहा है लेकिन मैं आज यहां यह कहने आया हूं; बस बहुत हो गया। नेतन्याहू ने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल को धरती पर हूए हमामस के हमले के प्रति अपने देश की जवाबी कार्रवाई का बचाव किया। हमामस के हमले की प्रतिक्रिया में चलाए गए इजराइली सैन्य अभियान ने गाजा पट्टी को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने कहा, इस साल मैं यहां नहीं आना चाहता था। मेरा देश अपना अस्तित्व बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जब कई वक्ताओं द्वारा इस मंच से मेरे देश पर लगाए गए झूठे आरोप और (उसकी) बदनामी को मैंने सुना, तो यहां आने और सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल शांति चाहता है, लेकिन ईरान के बारे में कहा, यदि आप हम पर हमला करेंगे, तो हम आप पर हमला करेंगे। उन्होंने एक बार फिर, क्षेत्र की कई समस्याओं के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने कहा कि लंबे समय से दुनिया ईरान को खुश करने में लगी हुई है और यह तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए। गाजा की हमामस सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इजरायल के हमलों में 41,500 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और 96,000 से

अधिक घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा, यह युद्ध अब समाप्त हो सकता है। बस इतना कि हमारा आत्मसमर्पण कर दे, अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम लड़ेंगे, जब तक कि हमें पूर्ण विजय नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइली सेना ने हमामस के 90 प्रतिशत रॉकेट स्टॉक कर दिए हैं और उसकी आधी सेना को मार दिया है या पकड़ लिया है। हाल के दिनों में, इजराइल ने अपना ध्यान लेबनान की सीमा पर केंद्रित किया है, जहां वह हिजबुल्ला के चरमपंथियों को निशाना बना रहा है और नागरिकों को भी हताहत कर रहा है। इस तरह, इजराइल दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तो गाजा पट्टी में और दूसरा लेबनान से लगी सीमा पर।

भीषण धमाकों से बेरूत दहला, हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हवाई हमले जारी

भाषा। बेरूत

इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला के केंद्रीय मुख्यालय पर एक हवाई हमला किया, जहां एक भीषण विस्फोट के कारण चार इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं तथा आसमान में नारंगी और काले रंग के धुएँ का गुबार छा गया। बेरूत के उपनगर दाहिया में यह हमला, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के कुछ ही समय बाद हुआ। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में संकल्प लिया कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल का अभियान जारी रहेगा। विस्फोट से कुछ समय पहले, उपनगर में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर सहित तीन सदस्यों को



अंतर्घुष्टि के लिए हजारों लोग एकरा हुए थे। हमले में हताहत हुए लोगों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। इजराइली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इसने आवासियों इमारतों के नीचे स्थित हिजबुल्ला के मुख्यालय को निशाना बनाया। हिजबुल्ला के अल-

मनार टेलीविजन के अनुसार, विस्फोट में चार इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित इमारतें भी हिल गईं। विस्फोट स्थल की ओर पहुंचेंसों को जाते देखा गया।

विवक न्यूज

शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन पूर्व नियोजित था: यूनुस

न्यूयार्क। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कस कि देश ने हाल में हुआ छत्र आंदोलन पूर्वनियोजित था और इसके कारण शेख हसीना को सत्ता से बाहर लेना पड़ा था। विल्टन ग्लोबल इनिशिएटिव की वार्षिक बैठकमें छात्रों का परिचय करते हुए ग्लोबल पुस्कर से सम्मानित यूनुस ने कस कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अगामी लीग के खिलाफ आंदोलन की योजना बनवाई गई थी। बैठकमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यूनुस का स्वागत किया। यूनुस (84) ने बांग्लादेशी छात्र नेताओं का परिचय करते हुए कस, संपूर्ण प्रति के पीछे इन्हीं लोगों का दिगमन माना जाता है। वे किसी अन्य युवा व्यक्तित्व की तरह दिखते है, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उन्हें कस करते हुए देखेंगे, जब आप उन्हें बोलते हुए सुनेंगे, तो आप चाप आओंगे। उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यूनुस ने विशेष रूप से छात्र कार्यकर्ता मस्युद अदुल्ला वी और इशारा विका और कस कि इस इश प्रमति के पीछे उनका दिगमन था। उन्होंने कस, वह बार-बार इससे इनकार करते है, उन्होंने गुझे नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को बताया है लेकिन इस तरह उन्हें पहचाना जाता है कि पूरी प्रमति के पीछे उनका ही दिगमन है। उन्होंने कस कि जब पिछली सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो परटनकरवी छात्र साहसपूर्ण गोलियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने कस कि देश ने सभी ने नाए बांग्लादेश का समर्थन किया।

फरवरी में जुटेंगे इलेक्ट्रिकल उद्योग से जुड़े उद्योगपति

पू्पी। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन इगमा ने इलेक्ट्रिकल एवं संबंधित उद्योग के लिए कालिंटि कैंपेन का आयोजन किया। इगमा आगामी 26 से 28 फरवरी 2025 में इलेक्टमा का आयोजन करेगा। यह आयोजन वाटर नोजडा में किया जाएगा। इसकी जानकारी इगमा के चेयरमैन सुनील साधवी ने दी। इस अवसर पूर्व चेयरमैन हनमन, डीजी चारु माश्रू भी उपस्थित रही। इसका जिसका उद्देश्य उपकरण निर्माण उद्योग में गुणवत्ता,सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की यह पहल भारत के विद्युत उपकरण निर्यात को बढ़ावा देती है, जो वार्षिक रूप में 12 बिलियन डॉलर है। औपस्थेयन राजनीतिक परिस्थितियों और चाइना प्लस । पॉलिसेी के गठनजएर मैनुफैक्चरिंग में चीन के विकल्पों की तलाश के बीच भारत निर्माण के मुख्य गंतव्य के रूप में उभर रहा है और नेक इन इंडिया एर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहे है। यह पहल विद्युत उपकरणों एवं कम्पोजेन्स के निर्माण में गुणवत्ता के मानक स्थापित करने की प्कनऱ। सुनिश्चिता के लिए मिश्रण और ऑपरेशन न्यूट्रल के प्रतीकन है किया गया था। पहल विद्युत उपकरणों के दृष्टिकोण के 75000 कएडर का निवेश किया गया है। एक अनुमान के अनुसार कश्चय में विद्युत की मांग 2028 तक 53,000 मेगावॉट तक पहुंच सकती है। ऐसे घेमें पावर सेक्टर तकनीकी प्रमति एवं विकास को नई गति प्रदान करेगी। सुनील सिक्ली जेफेडेन्टर ने आज के परिस्थर्षी दौर में गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए कस कि आज के दौर के उपभोगा अन्तररष्ट्रीय मानकों से गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स की मांग करते है। आद्येयन चौथी बार और नोजडा में विद्युत की मांग 2028 तक 53,000 मेगावॉट तक पहुंचेगी। दुनिया के सबसे बड़े इस शो में 1100 से अधिक परदर्शक 400000 आगंतुक हिस्सा लेंगे। 15000 से अधिक बीबीसी बैठकें लेनी 80 देशों से 600 से अधिक खरीददार पहुंचेंगे तथा 10 से अधिक देशों के पैरिलियन होंगे।

कनाडा के सांसद ने कनिष्क बम विस्फोट की नाए सिरे से गांच की मांग वाली याचिका की निंदा की

ओटावा। कनाडा ने भारतीय मूल के एक प्रमुख सांसद ने 1985 में एअर इंडिया उड़ान 182 में हुए बम विस्फोट की नाए सिरे से गांच की मांग वाली याचिका की आलोचना की तथा आरोप लगाया कि यह खालिस्तानी चरमपंथियों के ध्वंस्त सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला है।याचिका ने गांच की मांग इसलिए की गई है ताकि किसी विदेशी सुषिष्टा एजेंसी की सल्लिखता प पता लगाया जा सके।नॉर्वेजियन-नई दिल्ली एअर इंडिया दैनिक उड़ान संख्या 182 में 23 जून 1985 को लंदन के सैश्री हवाई अड्डे पर उरनेसे से 45 मिनट पहले विस्फोट से गया, जिससे विमान ने सवार सभी 329 लोग मारे गए। विमान ने सवार अधिरेष्ठ लोग भारतीय मूल केकनाडऱऱे इस बम विस्फोट का आरोप सिध्द चरमपंथी उवावर्तियों पर लगाया गया था, जो 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकलने के लिए मिश्रण और ऑपरेशन न्यूट्रल के प्रतीकन है किया गया था।नेपियन क्षेत्र से सांसद चंद आर्य ने बृहस्पतिवार को हाउस ऑफ कॉमन्स ने कस कि दो कनाडऱऱे गांचो में पाया गया है कि एअर इंडिया के विमान ने बम विस्फोट के लिए खालिस्तान चरमपंथी जिन्मेदार है।इस बम विस्फोट के घटिका के प्रतिनिधस का सबसे प्कनऱऱे हिस्सावडऱ बंताते हुए आर्य ने कस, आज भी, उस आतंकवादी हमले के लिए जिन्मेदार विचारस्थ कनाडा में कुछ लोगों के बीच जीवित है। उन्होंने कस, कनाडा की दो सार्वजनिक गांचो में पाया गया कि एअर इंडिया विमान ने बम विस्फोट के लिए खालिस्तानी चरमपंथी जिन्मेदार है। आ संसद के पोर्टल पर एक याचिका के प्रयास है। याचिका ने कनाडा के प्रतिनिधस का सबसे प्कनऱऱे विस्फोट की नाए सिरे से गांच का आदेश देने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसने कोई विदेशी सुषिष्टा एजेंसी शामिल थी।

कैथोलिक चर्च में यौन शोषण की घटनाओं को छिपाने के लिए बेल्जियम के प्रधानमंत्री पोप पर बरसे

ब्रसेल्स। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कैथोलिक चर्च में यौन शोषण की घटनाओं को छिपाने की भयावह परिष्ठाटी को लेकर पोप फ्रांसिस पर निशाना साधते हुए इस सिलसिले में ठोस कदम उठाने तथा पीड़ितों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने शुक्रवार को फ्रांसिस की यात्रा की शुक्रास्त के मौके पर यह बात कही। क्रू का भाषण, पोप की किसी विदेश यात्रा के दौरान उनपर आ बस तकिए का सबसे तीखे भाषणों में से एक था, जबकि राजनयिक प्रोटोकॉल के अनुसार सार्वजनिक भाषणों से आग्नेय थे। आमतौर पर दूर सजा जाता है। राजा फिलिप ने भी फ्रांसिस के लिए कई शब्दों का इस्तमाल किया था और उन्होंने चर्च से प्रायश्चित्त करने और पीड़ितों को उबारने में मदद करने के लिए अनवशत काम करने की मांग की थी। फ्रांसिस ने क्रू के भाषण के अंत में तालियां बजाई और शुक्रवार को ही से उनके अचेतने में मिलने की उम्मीद है। क्रू ने कस, आज केवल शब्द पर्याप्त नहीं है। हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने राजपरिषद के सदस्यों, चर्च के पदाधिसरतियों, राजनयिकों और राजनेतोंओ समेत अन्य श्रोतओं से समक्ष कस, पीड़ितों की आवाज सुनने की जरूरत है। उनमें चर्च में रखने की प्कनऱऱे विस्फोट की नाए सिरे से गांच का आदेश देने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसने कोई विदेशी सुषिष्टा एजेंसी शामिल थी।

जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस, महासभा अध्यक्ष यांग से मिले

भाषा। न्यूयॉर्क

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के नए अध्यक्ष फिलेमोन यांग से अलग-अलग मुलाकात की तथा विविधता में एकता , शांति एवं मानव कल्याण के यांग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं और उन्होंने बृहस्पतिवार को महासभा के सत्र से इतर गुतारेस तथा यांग से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुतारेस से मुलाकात करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संयुक्त



राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ बात करना हमेशा खुशी की बात होती है। भविष्य के लिए समझौते, बहुपक्षवाद में सुधार, एआई, जलवायु कार्रवाई, पश्चिम एशिया और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की। बैठक पर महासचिव के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा जारी संदेश में कहा गया कि गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत

के सहयोग की सरहना की। दोनों नेताओं ने 22–23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन और इसके कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भूराजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। वे सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने तथा समकालीन दुनिया की

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा

संयुक्त राष्ट्र। पाकिस्तान ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत को अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधानों को हटाने के फैसले को वापस लेना चाहिए और मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उसके (पाकिस्तान) साथ बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में 20 मिनट से अधिक के अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया साथ ही अनुच्छेद 370 और आतंकवादी संगठन हिज्बुल



मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी का संदर्भ दिया। शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि फलस्तीन के लोगों की ही तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। शरीफ ने अनुच्छेद 370 के

अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के भारत के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि स्थाई शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को आगस्त 2019 के एकरतरणा और अवैध कदमों को वापस लेना होगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों तथा कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी होगी। शरीफ ने आरोप लगाया कि शांति की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय भारत जम्मू-कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है।

अमेरिका के दक्षिण में हेलेन तूफान के साथ बारिश, बिजली भी गुल

कॉफोर्डविले। अमेरिका के फ्लोरिडा में हेलेन तूफान के तट पर दस्तक देने से भारी तूफानी लहरें उठीं और लाखों उपभोक्ताओं के घरों में बिजली गुल हो गई। बाढ़ग्रस्त घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए शुक्रवार को आपातकालीन दल यहां पहुंचा और मौसम संबंधित घटना से कम से कम छह लोगों के मारे जाने की खबर है। तूफान ने बृहस्पतिवार की देर रात बिग बॅंड ग्रामीण क्षेत्र में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाओं के साथ मछुआरों के गांव और छुट्टी मनाने के ठिकाने में दस्तक दी और उत्तरी कैरोलिना



तक बाढ़ आ गई। इस बीच जॉर्जिया के एक प्रांत में लगभग पूरी तरह से बिजली गुल रही।सोशल मीडिया मंच पर वीडियो में दिखाया गया कि

बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए शुक्रवार सुबह पहला बचाव दल नावों पर रवाना हो गया। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में लगभग 40 लाख घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिना बिजली के थे। फ्लोरिडा में एक साइनबोर्ड के कार पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तूफान के आने पर दक्षिण जॉर्जिया में संभावित बवंडर में दो लोगों के मारे जाने की खबर आई। उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट और दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन प्रांतों में घरों पर गिरे पेड़ों से मौतें हुईं हैं।

उम्रदराज महिलाओं का कोई भविष्य नहीं, सौंदर्य के मानकों से जुड़े भय को दर्शाया

द सम्बंटेस फिल्म

भाषा। सिडनी

द सम्बंटेस फिल्म में एक पूर्व अभिनेत्री एलिजाबेथ स्प्याक (डेमी क्रू) का करियर बढ़ती उम्र के साथ एक टेलीविजन नेटवर्क पर एरोबिक्स का प्रशिक्षण देने वाली महिला के तौर पर सिमट कर रह जाता है और उसके 50वें जन्मदिन पर नेटवर्क का कार्यकारी अधिकारी हार्वे क्रैंड उसे नौकरी से निकाल देता है। उम्रदराज महिलाओं का कोई भविष्य नहीं है- नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद एलिजाबेथ एक हादसे का शिकार हो जाती है और अस्पताल में एक खूबसूरत युवा डॉक्टर उसे काला बाजार में उपलब्ध एक ऐसी दवा के बारे में बताता है, जिसे द सम्बंटेस के नाम से जाना जाता है और उसका एक

ही इंजेक्शन व्यक्ति को युवा बना देता है। फिर से जवान दिखने के लिए बेताब एजिलाबेथ इस पदार्थ का सहारा लेती है जिससे उसके युवा संरक्षण सु (मार्गेट क्याल्स) का जन्म होता है। सम्बंटेस को लेने के कुछ दिनों में। इसका एक नियम यह है कि एलिजाब्रे यह फिल्म नारी की सुंदरता और यौवन के प्रति उसकी सनक, उम्रदराज महिलाओं को नजरअंदाज किए जाने और हॉलीवुड की स्टर प्रणाली में महिलाओं की शारीरिक सुंदरता के अत्यधिक इस्तेमाल की समस्याओं का उदाती है। फिल्म निर्देशक कोरली फारोेट ने साक्षात्कारों में सौंदर्य से जुड़े इस मिथक पर निशाना साधा है कि एक महिला की अहमियत उसके रूप से जुड़ी होती है। साथ ही उन्होंने फिल्म के जरिए पुरुष की उस दृष्टि पर भी कटाक्ष किया है जो नारी के शरीर को

पौष्टिक आहार से फिट रहता है स्वास्थ्य
सेहतमंद राष्ट्र के लिए नागरिकों के जीवन को बदलने में मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण आवश्यकताओं का समर्थन करने वाली एक अगामी कंपनी एम्बे इंडिया ने पूरे देश में लक्षित उपायों के साथ राष्ट्रीय पोषण माह मनाया। इस वर्ष के विषय सभी के लिए पौष्टिक आहार के साथ संरेक्षित इस पहल ने दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने को बढ़ावा देकर मजबूती भर खाने वाली इस पहल का उद्देश्य वितरकों को मजबूत किया। संतुलित आहार दिन की सभी शुरुआत के लिए सुबह का पौष्टिक आहार, गुणवत्तापूर्ण उपादों द्वारा समर्थित आवश्यकता.आधारित पोषण संबंधी सिफरिंटें और खान पाने की स्वस्थ युक्तियों को बढ़ावा देकरमजबूती भर खाने वाली इस पहल का उद्देश्य वितरकों को ज्ञान और जरूरी उपकरणों से लैस करना था ताकि वे स्ट्र और अपने बाहकों को सृष्टित आहार वितरण बनाने और र्थायी स्वास्थ्यवर्धक आदतें बनाने में मदद कर सकें। एम्बे इंडिया ने राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पोषण.आधारित लक्षित उपायों के माध्यम से देश भर में 30,000 वितरकों और उनके बाहकों को इस कार्यक्रम से जोड़ा। एम्बे इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश पोपड़ा ने इस अवसर परबोलते हुए कस कि श्युकि पोषण संबंधी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं इसलिए संतुलितपोषण को सभी के लिए सुलभ और र्थावस्थिक बनाना अत्यावश्यक हो गया है। इंडियन कांसिल ऑफ नैडिकल रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बीमारी के बोझ में 56.4योगदान अस्वास्थ्यकर आहार का है। जीवनशैली आधारित बढ़ती बीमारियों और उपभोगा की बदलती जरूरतों के साथपोषण को प्राथमिकता देना इष्टतम

57 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित
लोक की कमी से होने वाली रक्ताल्पता आईडीए जैसी व्यापक स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए पीडित ही हेल्थ ने भारत के अगामी स्वास्थ्य सेवा संघों में से एक टू फेडरेशन ऑफ ऑक्सटेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ़ इंडिया एम्बोजीएसआई के सहयोग से एक नया अभियान 12 का नाराशु शुरू कियाहै। राष्ट्रीय पहियार स्वास्थ्य संवेक्षण एनएएफएस.5 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 57 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित है, जिसमें से कई मामलों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक कि वे गंभीर नहीं हो जाते है। जागरूकता और कार्रवाई के बीच की खाई को पारने के लिए 12 का नारू तैयार किया गया है, जो 12 के एक्सी हतर को इष्टतम बनाए रखने के महत्व पर फ़काश डालता है। और विशेष रूप से महिलाओं की रक्ताल्पता को शुरुआत में ही पता लगाने और शिक्षा को लक्षित करता है।पॉवर एंड गैबल हेल्थ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक लिभिंट थर्दे ने जोर देते हुए कस कि रक्ताल्पता हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रख है, इसलिए शुरुआत में ही इसका पता लगाना और प्रबंधन करने में ज़ा प्लीगिया बस यात्राएँ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान प्रयासों में सबसे आगे रहें है।

पुरुषों के लिए एक वस्तु के रूप में एक रिपरिज लगाई जाती है जिससे वह दो भागों में विभाजित हो जाता है।

शुरूआती दृश्य में, एक अंडे की जर्दी में एक रिपरिज लगाई जाती है जिससे वह दो भागों में विभाजित हो जाता है।

